

अमेरिका में भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है ट्रम्प को "डिपोर्टेशन" नीति का सख्ती से पालन करने के लिये

पिउ रिसर्च द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क ट्रम्प के इस निर्णय से सहमत हैं

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 13 फरवरी। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने और अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकन लोग इन क्षेत्रों में ट्रम्प की कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं।
प्यु रिसर्च सर्वेक्षण के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क उन व्यक्तियों को निवासित करने के प्रयासों को मंजूरी देते हैं जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें से 35 प्रतिशत लोग इस नीति का मजबूत समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, 58 प्रतिशत लोग सीमा पर अधिक सैन्य बल भेजने के पक्ष में हैं। जिसमें 35 प्रतिशत लोग इस निर्णय का मजबूत समर्थन करते हैं।
हालांकि, ट्रंप के आप्रवासन संबंधी कार्रवाइयों के अंशों के अन्य तत्वों को जनता ने ख़ास पसंद नहीं किया है। उदाहरण के लिए, केवल 47 प्रतिशत लोग ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसमें उन शहरों और राज्यों को दी जाने वाली संघीय निधि में कटौती करने

पर, ट्रम्प के "इमिग्रेशन" से संबंधित अन्य "एजेंड्याप्टिव आदेश" को यह समर्थन नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिये उन प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता (फण्डिंग) कम करने का निर्णय, जो ट्रम्प सरकार की "डिपोर्टेशन" नीति लागू करने में मदद नहीं करते, 52 प्रतिशत लोग इस आदेश के खिलाफ हैं।
श्वेत अमेरिकी ट्रम्प की इन नीतियों के पक्ष में हैं, पर, अश्वेत अमेरिकियों में इन नीतियों का ज्यादा समर्थन नहीं दिख रहा। एशिया मूल के अमेरिकी, हिस्पैनिक मूल अमेरिकी नागरिकों से ज्यादा समर्थन देते नज़र आते, सर्वे के अनुसार।
रिपब्लिकन पार्टी के 74 प्रतिशत सदस्य मानते हैं, सरकार डिपोर्टेशन नीति के तहत उपयुक्त कार्यवाही कर रही है। जबकि, 73 प्रतिशत डेमोक्रेट्स मानते हैं, ट्रम्प प्रशासन कुछ ज्यादा ही सख्ती दिख रहा है, "डिपोर्टेशन" के मामलों में।

का कहा गया है जो निवासन प्रयासों में सहायता नहीं करते, जबकि 52 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं। इसी तरह, केवल 44 प्रतिशत लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसमें अमेरिका में बसने की इच्छा रखने वालों के लिए शरण आवेदन पर रोक लगाने की बात की गई है, जबकि 55 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं।
जातीय और नस्लीय समूहों में भी ट्रंप की आप्रवासन नीतियों को लेकर अलग-अलग स्तर का समर्थन नज़र

आया है। इसमें श्वेत वयस्कों का समर्थन सामान्य रूप से अन्य समूहों की तुलना में अधिक है, खासकर अश्वेत वयस्क प्रशासन की कार्रवाइयों के प्रति सबसे कम समर्थन दर्शाते हैं। हिस्पैनिक (स्पेन आदि देशों के लोग) की तुलना में एशियाई अमेरिकन ने ट्रम्प की नीतियों के प्रति ज्यादा समर्थन दर्शाया पर उनकी संख्या श्वेत अमेरिकन से कम है। जातीय समूहों में समर्थन में भिन्नताएं होने के बावजूद, राजनीतिक ध्रुवीकरण की अब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
रिपब्लिकन के बीच, ट्रम्प की आप्रवासन कार्रवाइयों का समर्थन नस्लीय और जातीय लाइन से परे काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, लगभग 91 प्रतिशत श्वेत रिपब्लिकन निवासन में वृद्धि का समर्थन करते हैं, और 92 प्रतिशत सीमा पर सैन्य उपस्थिति बढ़ाए जाने का समर्थन करते हैं। हिस्पैनिक रिपब्लिकन का समर्थन कम है, जिसमें केवल 69 प्रतिशत लोग निवासन बढ़ाने का समर्थन करते हैं और 75 प्रतिशत सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बलों का समर्थन करते हैं। श्वेत रिपब्लिकन ने हिस्पैनिक रिपब्लिकन की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। केंद्र सरकार ने डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से हिंसा की घटनाओं से जूझ रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरन सिंह द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति

मणिपुर के राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की।

को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट और अन्य जानकारी पर विचार करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा के सभी अधिकार राज्यपाल की शक्तियों के तहत आ जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में पिछले डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को यकीन है, ट्रम्प से मैत्री के कारण मोदी टैरिफ और व्यापार की दिक्कतों को लांघ जाएंगे

भारत को उम्मीद है कि मोदी और ट्रम्प की मैत्री दोनों देशों की राजनीतिक साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाएगी



देश को विश्वास है कि मोदी की अमेरिका यात्रा में पहले की भांति मोदी और ट्रंप के संबंध मददगार साबित होंगे। टैरिफ व व्यापार की दिक्कतों को दूर करने के लिए।

वॉशिंगटन, 13 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंच गये हैं। इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प, अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों और उद्योग जगत के नेताओं के

साथ बातचीत करेंगे। मोदी ने गुरुवार तड़के 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वे ट्रम्प के साथ अपनी बातचीत और व्यापक द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लिखा कि, थोड़ी

वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, वे डॉनल्ड ट्रम्प से मिलने और भारत अमेरिका के बीच वैश्विक साझेदारी बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक हैं।
प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं, जहाँ भारी तादाद में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया।

देर पहले वॉशिंगटन डीसी में उतरा हूँ। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प से मिलने और भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। दोनों देश अपने लोगों के लाभ और हमारी दुनिया के बेहतर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गौतम अडानी ने श्रीलंका के एक अरब डॉलर के पवन ऊर्जा प्रोजैक्ट से "विड्रॉ" किया

चर्चा है कि इस प्रोजैक्ट से हटकर वे मोदी सरकार को, एक और, "विवाद में पड़ने से बचा लेंगे

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 13 फरवरी। मोदी सरकार को और किसी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए, गौतम अडानी के समूह की रिन्यूबल एनर्जी कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में प्रस्तावित दो पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि श्रीलंका की नई सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कड़ी नीतियाँ अपनाई हैं।
कंपनी ने एक बयान में कहा, "अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी बोर्ड की बैठक में श्रीलंका में रिन्यूबल एनर्जी विंड एनर्जी (पवन ऊर्जा) परियोजना और दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं का आगे का काम रोकने का निर्णय लिया है।"
अडानी ने राजपक्ष के नेतृत्व वाली पूर्व श्रीलंकाई सरकार के कार्यकाल में ये प्रतिष्ठित परियोजनाएँ हासिल की थीं। राजपक्ष शासन को बड़े पैमाने पर लोगों के विरोध के कारण उखाड़ फेंका गया

जब अडानी ग्रुप को यह प्रोजैक्ट मिला था, तो माना जा रहा था कि भारत सरकार की मदद से अडानी ग्रुप को यह प्रोजैक्ट मिला था।

उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्ष थे, पर, उनका तख्ता पलट कर, वामपंथी विचारधारा के नज़दीकी माने जाने वाले दिशानायक नये राष्ट्रपति बने और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लगावाये गये सभी प्रोजैक्ट की नये सिरे से छानबीन शुरू कर दी।

अडानी की कम्पनी ने श्रीलंका को अपने प्रोजैक्ट से 0.0826 डॉलर प्रति किलोवाट घंटा की रेट से बिजली देने का अनुबंधन किया था, पर जब से अडानी के खिलाफ अफसरों को रिश्तत देकर, भारी दाम पर बिजली बेचने का अभियोग पत्र दाखिल हुआ, श्रीलंका ने अनुबंधन को नये सिरे से देखना शुरू किया, तथा नई रेट 0.06 प्रति यूनिट निश्चित करने की तैयारी कर ली थी।

था। अब राष्ट्रपति अनुरा कुमारा गठबंधन सरकार पूर्व सरकार की सभी दिशानायक के नेतृत्व वाली नई वामपंथी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा की कार्यवाही दस मार्च तक स्थगित

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। बजट सत्र का प्रथम चरण पूरा होने के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिये स्थगित कर दी गयी। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले कहा कि बजट सत्र के प्रथम चरण के दौरान अच्छे वातावरण में चर्चा की गयी। सदन की कार्यवाही उत्पादकता 112 प्रतिशत रही।

स्पीकर ओम बिड़ला ने बजट सत्र में सांसदों का सक्रिय भागीदारी करने के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में 17 घंटे 23 मिनट तक सार्थक चर्चा की गयी और इसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया।
बिरला ने कहा कि इसी तरह बजट पर 16 घंटे 13 मिनट तक चर्चा की गयी और इस दौरान 170 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभायी।
उन्होंने कहा कि वे अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह सदस्यों के सहयोग से सदन की कार्यवाही आगे भी सुचारु रूप से चलेगी।

'आर.पी.एस.सी. के अफसरों के पेपर लीक में लिप्त होने के कारण एस.आई.भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करना गलत उदाहरण स्थापित करेगा'

राज्य सरकार का यह भी कहना है कि एक परीक्षा रद्द करने से गिरफ्तार आर.पी.एस.सी. अफसरों की देखरेख में की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का दबाव बढ़ेगा

—यादवेंद्र शर्मा—
जयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में एस.आई.भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कई अवांछित कारणों से प्रेरित होकर याचिका दायर की हैं और याचिकाकर्ताओं का अपनी याचिका में यह संकेत करना कि राज्य सरकार मामले में जांच नहीं चाहती और परीक्षा रद्द करने के खिलाफ है, बिल्कुल ही बेवुनियाद है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले एस.आई.टी. द्वारा इसकी जांच कराई, फिर जांच के दौरान आर.पी.एस.सी. अफसरों की गिरफ्तारी करने में कोई संकोच नहीं दिखाया, महाधिवक्ता द्वारा इसी मामले पर विधिक सलाह भी ली और फिर छह मंत्रियों की जांच कमेटी भी बनाई। और

ज्ञातव्य है कि आर.पी.एस.सी. अफसरों की गिरफ्तारी के बाद ही महाधिवक्ता ने सलाह दी थी कि परीक्षा को रद्द किया जाये।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने महाधिवक्ता की राय और एस.ओ.जी.की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कई अभ्यर्थी भी एस.आई.भर्ती के तहत पुलिस में शामिल हो गए हैं, इसलिये यह पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिये।

राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता भी मामले में लाभार्थी हैं और उन्होंने कई तथ्य छुपाकर याचिका दायर की हैं। जिससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि पिछली गहलोत सरकार में रीट परीक्षा की जांच के लिये दायर की गई याचिकाओं की तरह ही, एक बार याचिकाओं के रद्द हो जाने के बाद किसी भी बड़े अधिकारी या नेता को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जांच में भी हिलाई आ जायेगी।

आज राज्य सरकार के समक्ष इस मामले में परीक्षा रद्द करने का फैसला

विचाराधीन है इसलिए याचिकाकर्ताओं की याचिका अपरिपक्व भी है।
उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता के समक्ष ये सभी तथ्य मौजूद थे और सभी कानूनी जटिलताओं की जानकारी थी, उसके बावजूद उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह परीक्षा को रद्द करे और 2022 के विधान के अनुसार पुनः परीक्षा ले, ताकि अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सके। न्यायाधीश समीर जैन ने भी बहस के दौरान महाधिवक्ता द्वारा दी गई विधिक सलाह का जिक्र किया और कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.पी.एस.सी. के कानून और उस पर राज्य सरकार के रूख के संदर्भ में जानकारी दें। कल यह बहस जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एस.आई.भर्ती परीक्षा 2022 में ही दे दी गई थी, परंतु सितम्बर 2023 में ही दे दी गई थी, परंतु (शेष अंतिम पृष्ठ)

कृषि उपज मंडियों के लिए 24 करोड़ रूपए स्वीकृत

जयपुर, 13 फरवरी। किसानों एवं व्यापारियों के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि उपज मण्डी समिति लालसोत, भवानीमण्डी, देवली

मु.मंत्री भजनलाल ने मंडियों के विकास कार्य के लिए यह राशि स्वीकृत की है।

एवं कोटपतली में आधारभूत ढ ंचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही, कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर (अनाज), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर, खाजूवाला, श्रीमाधोपुर, नोखा, श्रीहराराद एवं पदमपुर में सम्पन्न सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। शर्मा द्वारा (शेष अंतिम पृष्ठ)

जाने-माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत के लिए अब नया टारगेट है तमिलनाडु?

चर्चाओं के अनुसार, प्रशांत किशोर ने युवा फिल्म अभिनेता विजय से मुलाकात करके, तमिलनाडु की राजनीति में नई भूमिका की तलाश शुरू की है

—लक्ष्मण वैकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 13 फरवरी। राजनेता प्रशांत किशोर के भीतर के राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी नज़रें तमिलनाडु की तरफ कर ली हैं। इस दक्षिणी राज्य में हालात यह है कि यहाँ कि एक प्रमुख द्रविड़ पार्टी अन्नाद्रमुक जो मुख्य विपक्षी दल भी है, बहुत कमजोर हो गई है। खासकर विभाजन के बाद। इसके अलावा भाजपा, जिसने वहाँ छोटे-छोटे दलों का गठबंधन बनाया है, को लगता है कि वह अन्नाद्रमुक की जगह ले सकती है और आगामी चुनाव में द्रमुक का सामना कर सकती है। एक ऐसा राज्य जहाँ राजनीति का

फिल्मों से गहरा संबंध है, वहाँ प्रशांत किशोर ने एक्टर विजय से मुलाकात की। विजय ने हाल ही में अपने राजनैतिक इरादे खुलकर जाहिर किए हैं। वे राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक खालीपन है, जिसमें एक युवा एवं ऊर्जावान राजनेता वह नया बदलाव ला सकता है, जिसके लिए यह राज्य तरस रहा है।
यह तो कोई नहीं जानता कि अगर एक्टर विजय ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की तो उससे किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। एक्टर विजय और प्रशांत दोनों ने ही इस मुलाकात पर ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने

तमिलनाडु की राजनीति में अजीबो-गरीब स्थिति है। प्रमुख द्रविड़ पार्टी अन्नाद्रमुक लगातार अपना वोट खोती जा रही है। फिल्म स्टार विजय का मानना है कि 2026 के चुनाव में एक युवा नेता ही इस "वैक्यूम" को भर सकता है।
इस महत्वाकांक्षा के तहत ही विजय, पूरे प्रदेश में अप्रैल माह में, एक सघन जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे तथा जगह-जगह ऑफिस खोलेंगे तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे।
क्या प्रशांत, विजय व अन्नाद्रमुक को एक ही मंच पर लाने का काम करेंगे, जिसमें भाजपा की भी भूमिका हो सकती है।
तीन पार्टियाँ: विजय, अन्नाद्रमुक व भाजपा अच्छी तरह जानती हैं कि अगर कोई गठबंधन नहीं हुआ और विजय अकेले ही लड़े तो एन्टी द्रमुक वोटों का विभाजन होगा और द्रमुक और मजबूत होगी और फिर ढाक के वो ही तीन पात रह जायेंगे।
कहा, यह शिष्टाचार मीटिंग थी। यह मुलाकात विजय की पार्टी के प्रचार प्रमुख आश्वव अर्जुन ने आयोजित की थी।

फिलहाल विजय अपनी पार्टी टीवीके का जनाधार बनाने में लगे हैं और पूरे राज्य में इसका नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इससे भी उनके इरादों का संकेत मिलता है। विजय तमिलनाडु में एक राजनैतिक ताकत बनना चाहते हैं और चुंकि अन्नाद्रमुक की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए विजय की पार्टी के सफल होने की संभावना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर अन्नाद्रमुक के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, इन अफवाहों को देखते हुए कि प्रशांत किशोर इस बार जनाता की अदालत में अन्नाद्रमुक का पक्ष रखेंगे। अन्नाद्रमुक, किशोर के साथ डील साईन करने के बेहद करीब है। पर सीधे (शेष अंतिम पृष्ठ)

समरावता में ग्रामीणों पर कार्यवाही, हाई कोर्ट ने केस डायरी मांगी

जयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनीयारा विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थपसू मारने की घटना के बाद समरावता में ग्रामीणों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर

समरावता में ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार पर प्रशासनिक कार्यवाही की सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केस डायरी तलब की है।

सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार से केस डायरी तलब की है। जस्टिस विनोद कुमार भारवाणी ने यह आदेश दिलखुश मीणा व (शेष अंतिम पृष्ठ)

विचार बिन्दु

हर चीज बदलती है, नष्ट कोई चीज नहीं होती। -अरविन्द घोस

अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजना न केवल अवैध था अपितु अमानवीय भी तथा इस बाबत धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 असंवैधानिक है

अमरीका में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है जो अवैध रूप से घुसते हैं और बीजा नियमों की अवज्ञा करते हैं, अथवा ऐसे लोग हैं जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं, किन्तु बीजा की मियाद के बाद रूकते हैं तथा जो पैरोल की अवधि के बाद जेल नहीं लाते व ऐसे लोग हैं जिसका कानून के अनुसार अधिकार था, किन्तु दस्तावेजगत का नवीनीकरण उन्होंने नहीं कराया। लगभग सभी देशों में यही नियम है। अवैध भारतीय प्रवासियों को उनके देश भारत भेजना डिपोट करना कलता है। अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रम्प ने शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त सामूहिक निर्वासन की घोषणा की है और उन्हें एक अमेरिका सैन्य सी-17 विमान से 104 भारतीयों को भारत भेजा है, यह विमान अमृतसर उतरा है। इनके हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़ी थी, मानो वे गुलाम हों, उन्हें भूखा प्यासा भी रखा गया। उन्हें इस प्रकार भेजा जावेगा इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं दी गई। प्रत्येक देश अपने नागरिकों को वापिस लाता है। भारत अपने लोगों को वापिस लाता रहा है। अमेरिका में 17940 भारतीय हैं, जिनके पास रहने के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। गत वर्ष 1529 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापिस भेजा था। भारत में भी घुसपैठिये बहुत हैं, जिन्हें निर्वासित किया जाना है। एजेन्ट घोषे से इन्हें सही रास्ते से नहीं अपितु 'डॉकी रूट' से भी ले जाते हैं। यात्रा में पहाड़ी भूमि और समुद्र तक आते हैं रास्ते विकट होते हैं। डिपोट भारतीयों ने आरोप लगाये कि अमेरिका में उनके साथ कैदियों से भी खराब व्यवहार किया जाता है। इन्हें सैन्य विभाग में भी बहुत कष्ट दिये गये। अमानवीय व्यवहार किया गया।

अमरीका से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी बांध कर भेजने पर दोनों सदनों में सरकार को घेरा और विदेश मंत्री जयशंकर को जबाब देने को बाध्य किया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि अमरीका का अवैध भारतीय प्रवासियों की निर्वासित करने की प्रक्रिया नई बात नहीं है, यह अमरीका के नियमों के अनुसार है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सभी देशों का कर्तव्य है कि उनके नागरिकों को वह अपने यहां लें। भारत सरकार कह चुकी है कि अवैध प्रवासियों को पहचान करने और उन्हें वापिस लेने के लिये ट्रम्प प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित किया जावे। डिपोट करने के लिये मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हिरासत केपमें में बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन न हो। संसद में इस संबंध में गम्भीर बहस हुई थी और संसदों ने यहां तक कहा कि पीएम मोदी ट्रम्प के अच्छे दोस्त हैं उन्होंने फिर ऐसा व्यवहार क्यों होने दिया? देश को ऐसे लोगों को अपने जहाज से लाना चाहिये था। प्रतिपक्ष के नेतृ ने कहा प्रधानमंत्री को इन लोगों का दर्द सुनना चाहिये। 40 घंटों तक हथकड़ी व बेड़ी में बंधे रहने की वेदना अवर्णनीय है। इस प्रकार की घटनायें उप-निवेशिक काल की याद को ताजा करती हैं।

हथकड़ी लगाने का प्रचलन लगभग 400 बीसी का है। उस समय युद्ध के बंधियों को कन्ट्रोल किया जाता था। वर्तमान समय में हथकड़ी का उपयोग 1912 से किया जाने लगा, जब पुलिस स्टेशन से जेल, कैदियों को ले जाया जाता था या कोर्ट ले जाया जाता था और वापिस लाया जाता था। ब्रिटेन के शासन के समय उपनिवेशवादी सरकार स्वतंत्रता सैनानियों को हथकड़ी व बेड़ियों में इसलिये बांधकर रखती थी कि कहीं वे भागकर पुनः स्वतंत्रता आंदोलन में न जुड़ जायें। आजादी से पूर्व पुलिस एक्ट 1861 की धारा 12 में इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को अधिकार दिये गये थे कि वे इस बाबत नियम बना सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस रेगुलेशन बंगाल 1943 पारित किया और उसमें यह व्यवस्था दी गई कि हथकड़ी का प्रयोग केवल बहुत अधिक आवश्यक परिस्थितियों में ही होगा, तथा महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई जावेगी।

मानव अधिकारों की घोषणा के बाद से यह माना गया कि मानव की गरिमा अक्षुण्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अतः हथकड़ी लगाना अभद्र तरीका है, किन्तु पुलिस फिर भी अपनी शक्ति के घमण्ड में हथकड़ी का प्रयोग करती रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से स्पष्ट निर्देश दिया कि सामान्यतः हथकड़ी कैदी के नहीं लगाई जावेगी, क्योंकि ऐसा करना अमानवीय है तथा नारकीय कृत्य है। यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने हथकड़ी लगाने से मानव को मुक्त कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि सब मानव समान हैं, स्वतंत्र

हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी क्षमता के अनुसार व्यवहार नभिये किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित केसेज में प्रेमशंकर शुक्ला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 (3) एससीसी 526, एजाज रिजवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (निर्णय दिनांक 7.9.2010) एलमन श रेन एडवोकेट बनाम यूनिवर्स ऑफ इण्डिया (निर्णय दिनांक 4.8.1988), विनेश के एप बनाम स्टेट ऑफ केरल (निर्णय दिनांक 19.12.2008), खेदत मजदूर चेतना संघ बनाम स्टेट ऑफ एमपी (निर्णय दिनांक 9.9.1994) आदि निर्णयों में हथकड़ी लगाने को अनुचित तथा अमानवीय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार माना गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है केवल बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति में ही, कोर्ट की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। हथकड़ी लगाने को अनुचित व संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 के विरुद्ध कई निर्णयों में माना है। इसे व्यक्ति के गरिमामय जीने के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध अमानवीय व नारकीय माना है। कुछ केसेज में अधिकारी के विरुद्ध हथकड़ी लगाने पर कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निर्देश देश के कानून माने गये हैं। महिलाओं व बालकों को हथकड़ी व बेड़ी लगाने को न्यायालयों की आज्ञा की गम्भीर अवज्ञा माना है।

भारत के न्यायालयों ने हथकड़ी लगाने को व्यक्ति गरिमामय जीने के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध माना है इसे नारकीय (Cruel) व्यवहार भी कहा है। भारत UDHR ने स्वीकार किया है व वह कई अन्तर्राष्ट्रीय संघियों का हस्ताक्षरकर्ता है, फिर भी हथकड़ी के प्रयोग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को (नया कानून) धारा 43(3) BNNS, 2023 के माध्यम से Re-introduce किया है। क्या ऐसा किया सम्भव से परे है? धारा 43(3) में यह कहा है कि पुलिस उस धारा में बताये गये अपराध अथवा परिस्थिति में अपराधी को हथकड़ी लगा सकती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के एक दर्जन से भी अधिक केसेज में हथकड़ी लगाने को अनुच्छेद 14, 19 व 21 के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध माना है। कुछ भी हो धारा 43(3) BNNS, 2023 उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध होने से अवैध है, अमानवीय है व निरंकुश है। प्रार्थना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस मामले में संज्ञान लेना चाहिये और धारा 43(3) को अवैध करार देना चाहिये। यहाँ यह लिखना भी समीचीन व आवश्यक होगा कि धारा 43 BNNS, 2023 प्रस्तुत प्रकरण पर लागू ही नहीं है।

अमेरिका का सैन्य विमान 104 अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भारत लेकर आया वह भी हथकड़ी व बेड़ियों में और देश की सरकार जो विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति होने का दावा करती है वह केवल यह कहकर संतोष करती है कि पहले भी ऐसा होता आया है, सम्भव से परे है। हाँ, देश की संसद में इस घटना पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की गई है और उचित कदम उठाने का विश्वास सरकार ने दिलाया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि भारत ने अमेरिका से कहा है कि भारत अपने लोगों को स्वयं लेकर आयेगा। हमसे अच्छे तो ग्वाटेमाला, पेरू, मेक्सिको, कोलम्बिया के देश हैं जिन्होंने अमेरिका के विरुद्ध आवाज उठाई है। कोलम्बिया के राष्ट्रपति ने तो अमेरिका के सैन्य विमान को जो ऐसे लोगों को लेकर आया था, अपने देश के उतरने की अनुमति ही नहीं दी और अपनी शर्त पर ही भेजने पर उन्हें वापिस बुलाया।

भारत को अवैध इमीग्रेशन रैकेट पर भी कठोर कार्यवाही करनी होगी जो लाखों/करोड़ों रूपये लेकर भारतीयों को अमेरिका ले जाते हैं। भारत को यथासम्भव शीघ्र इस हेतु कानून बनाना होगा और उसको पालना सुनिश्चित करनी होगी।

यह मान्य सिद्धान्त है कि अवैध प्रवासियों को उनके देश डिपोट किया जाता है और जिस देश के वे नागरिक हैं वह उन्हें अपने यहां ले जावे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोट किया और यह भी नियम है कि भारत को उन्हें अपने देश यहां लाने की व्यवस्था करनी है, किन्तु यह भी सच है कि अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिका अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। जैसा ऊपर वर्णित किया है इन लोगों को सैन्य विमान से भेजा गया है, जिसमें केवल एक टायलेट था और हथकड़ी व बेड़ियों में बंधे हुये उन्हें उसका उपयोग करना होता था, जिसे बंद भी नहीं किया जाता है। यात्रा की दास्तान दर्दभरी है। यह अमानवीय व्यवहार था, नारकीय पीड़ा दी जाती थी। यह कृत्य मानव अधिकारों के सर्वथा विपरीत था। मानव अधिकारों के विरुद्ध था। यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 की आज्ञा के विरुद्ध था। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानव अधिकारों के विरुद्ध माना है। यहां यह लिखना समीचीन होगा कि मानव अधिकार वे ही अधिकार हैं जो संविधान के चैप्टर 3 व 4 में वर्णित किये गये हैं। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) अवैध व असंवैधानिक है। अतः शीघ्र ही इसे न्यायालय से अवैध घोषित कराकर निरस्त करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये, हथकड़ी व बेड़ी लगाकर डिपोट करना अवैध व अमानवीय है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। आवश्यक हो तो यूएनओ में भी इस हेतु उचित कार्यवाही की जानी चाहिये या इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस अमानवीय घटना के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिये।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि समावादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



राजेश भूषण

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी और तालिबान के पुनर्जन्म से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के साथ इस क्षेत्र का भू-राजनीतिक परिदृश्य अत्यधिक अप्रत्याशित परिवर्तन से गुजर रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में उथल-पुथल देखी जा रही है क्योंकि भारत एक तरफ अस्थिर बांग्लादेश से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने बदलते रिश्तों की गतिशीलता के अप्रत्याशित परिणामों से जूझ रहा है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध, जो कभी साझा इतिहास और आपसी हितों में निहित था, अब एक चिंताजनक स्तर तक बिगड़ गया है और तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी था, अब कई मोर्चों पर एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में बदल गया है। इस संबंध में गहरा बदलाव केवल तनावपूर्ण संबंधों का मामला नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण विकसित संबंध का आकार ले चुका है जिसमें सैन्य संघर्ष और ड्रूंड रेखा पर बढ़ता तनाव शामिल है।

अफगानिस्तान में तालिबान का उदय पाकिस्तान के ऐतिहासिक रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने शुरू में संयुक्त राज्य

अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को हथियार देने और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में अमेरिका और नाटो बलों का विरोध करने के लिए लॉजिस्टिक, सामग्री और नैतिक सहायता प्रदान की थी। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, अफगान-पाक घुरी के लिए कथित जीत का क्षण से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तान के लिए स्थिति उलट गई। तालिबान की सत्ता में वापसी ने क्षेत्रीय समीकरण को बदल दिया है। तालिबान ने अब आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना दर्शाते हुए पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में ड्रूंड रेखा को खारिज कर दो पुराने सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है।

अफगानिस्तान से संचालित हो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान के समर्थन में पहले से ही कमजोर पाक-अफगान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। वैचारिक मतभेदों और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ तालिबान के सहयोग की कमी के कारण आपसी विश्वास टूट गया है। वैश्विक इस्लामी आंदोलन का नेतृत्व करने की तालिबान की महत्वाकांक्षा और सीमाओं से परे अपने प्रभाव विस्तार में पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा में संरिखित कर तनाव को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ तालिबान के संबंध आश्चर्यजनक तरीके से विकसित हुए हैं, जिससे इस्लामाबाद में कई मोर्चे तन गए हैं। पाकिस्तान द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान करने में अक्षमता को देखते हुए नया तालिबान क्षेत्रीय आर्थिक समर्थन

हासिल करने में भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा है। यह आर्थिक और कूटनीतिक बदलाव पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है और इस क्षेत्र में भारत को प्राथमिक विरोधी के रूप में देखा है। चीन और रूस के साथ तालिबान के बढ़ते संबंध अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में बल देने में सक्षम बनाया जा सकता है, इस प्रकार भारत से संचालित खतरों के खिलाफ अफगानिस्तान का उपयोग पाकिस्तान के लिये मुस्किल हो जाता है। इन मुद्दों के साथ साथ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को जटिल बनाता है। देश की सेना कई आंतरिक संघर्षों में लगी हुई है, विशेष रूप से बलूचिस्तान में। क्षेत्र में सैन्य बल घरेलू सुरक्षा चिंताओं और तालिबान से बढ़ते बाहरी खतरों दोनों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में पाकिस्तान असमर्थ है, जिससे एक अनिश्चित स्थिति पैदा हो गई है।

ड्रूंड रेखा पर मतभेद, दोनों पक्षों में सैन्य संघर्ष में नुकसान परिणामस्वरूप, और तालिबान का टीटीपी के प्रति समर्थन, साथ ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरे वैचारिक मतभेद पाक-अफगान संबंधों को निम्न स्तर पर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक ऐसे समय में जब इसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पहले से ही नाजुक है, एक बहु-क्षेत्रीय संघर्ष में उलझे का जोखिम निश्चित रूप से भारत के लिये लाभकारी स्थिति है। भारत को अफगान-पाक सीमा के साथ बढ़ती अस्थिरता और पाक-अफगान संबंधों के निम्न स्तर के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय गतिशीलता का आकलन करना चाहिए। आर्थिक सहायता और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों में भारत - अफगानिस्तान के बढ़ते

संबंध पाकिस्तान के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर सकते हैं। एक मजबूत भारत-अफगान संबंध, विशेष रूप से पाकिस्तान की बढ़ती अलावा के संदर्भ में, भारत के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रभाव के नए अवसर पैदा करता है।

भारत को इस लाभदायक स्थिति का लाभ उठाने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति और रणनीतिक पूर्वदृष्टि के साथ एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। दक्षिण एशियाई भू-राजनीति के व्यापक संदर्भ में आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच फिल्टर बनाते हुए अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रा और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताफी के बीच हालिया बैठक ने अफगान नेतृत्व के साथ भारत के प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। भारत ने पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में सहायता और पुनर्निर्माण कार्य में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत का मुख्य ध्यान क्षेत्रीय विकास, व्यापार और मानवतावादी सहयोग है और साथ ही विकासोन्मुख परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और अफगानिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों को मदद हेतु एक समझौते पर है।

भारत को अफगान-पाक सीमा के साथ बढ़ती अस्थिरता और पाक-अफगान संबंधों के निम्न स्तर के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय गतिशीलता का आकलन करना चाहिए। आर्थिक सहायता और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों में भारत - अफगानिस्तान के बढ़ते

अनदेखी करना एक विकल्प नहीं है। भारत अपने ऐतिहासिक संबंधों और अफगानिस्तान के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करता है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि क्षेत्र में तालिबान के पुनरुत्थान के साथ भारत के लिए भी कट्टरपंथीकरण का खतरा बढ़ रहा है। भारत को एक ही टोकर में तालिबान के पुनरुत्थान के साथ भारत के लिए भी कट्टरपंथीकरण का खतरा बढ़ रहा है। भारत को एक ही टोकर में तालिबान के पुनरुत्थान के साथ भारत के लिए भी कट्टरपंथीकरण का खतरा बढ़ रहा है।

अन्य देशों की तरह भारत ने भी तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन नई दिल्ली फिर भी काबुल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन, पश्चिम के अफगानिस्तान प्रस्थान से पैदा हुए शून्य को ना भर सके। ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक कमजोरी और उजागर हो गई है। यह बंदरगाह अफगानिस्तान को पाकिस्तान के माध्यम से जाने की आवश्यकता के बिना वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। नतीजतन, अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि अफगान सामानों के लिए मुख्य पारगमन केंद्र के रूप में पाकिस्तान की भूमिका कम हो रही है। भारत के लिए, यह सही समय है कि वह पाकिस्तान और तालिबान के बीच विगड़ते संबंधों के दृष्टिगत अपने हितों को आगे बढ़ाए।

-राजेश भूषण, डाइरेक्टर, एडवैन्सपीएल, जयपुर

पांचवी बोर्ड अभ्यर्थियों का चार किलोमीटर के क्षेत्र में ही होगा परीक्षा सेंटर

शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किये, 33 जिलों के आधार पर होगी मुख्य परीक्षा

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों की पांचवी बोर्ड परीक्षा राज्य में 33 जिलों के डाइट के आधार पर कराई जाएगी।

5वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सदस्य जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित डाइट प्राचार्य होगा। वहीं, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 6 सदस्य ही ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

संबंधित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को अधिकतम चार किलोमीटर की दूरी तक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र में बदलाव करना हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा के बाद जिला नोडल अधिकारी के जरिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही केंद्र में बदलाव हो सकेगा।

5वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सदस्य जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी।

परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में दूसरी बार बढ़ाती की है। परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक

ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी। लेकिन निर्धारित तिथि तक आठवीं में करीब 10 हजार और 5वीं में 25 हजार अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में दूसरी बार बढ़ाती की है। परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक

छात्रहित में पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को तीन दिन के लिए बढ़ाया है। पंजीयक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी आवेदन से वंचित रहता है तो संबंधित स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में समस्त सीडीओ और डायट प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं।

पंजीयक 5वीं बोर्ड परीक्षा में अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं उन्नी राजकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जहां पहले से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

सहायक अध्यापक अब मानदेय से वंचित नहीं रहेंगे, निर्देश जारी

बीकानेर, (निसं)। राज्य के महात्मा गांधी इंटरकाॅलेजियल स्कूलों में राजस्थान कॉन्ट्रैक्टुअल हार्यरिग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लेवल वन और लेवल सैकंड के पदों पर सिविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापक अब मानदेय से वंचित नहीं रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक गोपाल राम बिड़ड़ा ने इस

महात्मा गांधी अग्रेजी स्कूलों में सिविदा पर नियुक्त हैं अध्यापक

संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त निदेशक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी सिविदा सहायक अध्यापक नियमों

के तहत पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने तथा मेडिकल व एनपीएस पुनर्भरण के लाभ से वंचित नहीं रहें। दरअसल, सिविदा सहायक अध्यापकों को शाला दर्पण पोर्टल पर मैपिंग कराए जाने संबंधित करवाई प्रक्रियाधीन है। सिविदा कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान हो इस संबंध में माॅनिटरिंग संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

“जल ग्रहण यात्रा” का आयोजन 15 फरवरी से

भीलवाड़ा, (निसं)। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जलग्रहण विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भीलवाड़ा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में “जल ग्रहण यात्रा 2025” का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जल ग्रहण घटक) के तहत 15 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से विभिन्न ग्राम पंचायतों और सामुदायिक स्थलों पर आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस यात्रा में सक्रिय भाग लें और जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाएं। आयोजन के लिए, तालिबान के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करना और चारागाह विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

पंजीयक 5वीं बोर्ड परीक्षा में अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं उन्नी राजकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जहां पहले से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

राशिफल शुक्रवार 14 फरवरी, 2025



पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:09 तक, अतिगंड योग प्रातः 7:10 तक, तैलिल करण प्रातः 9:07 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रातः 5:44 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सेन्ट वेलेंटाइन दिवस है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:31 तक, लाभ-अमृत 8:31 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:04 तक, चर 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 6:14

मेघ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आज परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

वृष
घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपसी मतभेद समाप्त हो सकती है। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

मिथुन
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक-मौलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आज परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज धन हानि का पथ है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उन्नावधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आज संचालित श्रौत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज अर्नाल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृश्चिक
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक बातों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मकर
शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

मीन
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

पटाखा गोदाम में आग लगने से 14 लोग झुलसे, दो की हालत गंभीर

आग लगने के बाद गोदाम में दो बड़े धमाके हुए और रह-रहकर पटाखों की गूज सुनाई देती रही

बांसवाड़ा, (निर्स)। बांसवाड़ा जयपुर मार्ग स्थित रिक्त औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से 14 लोग झुलसे हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर में गोदाम में लगी आग का धुआं शहर तक दिखाई दिया। नौ दमकलों की मदद से लगभग दो घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर डॉ. इन्द्रजीत सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला भी मौके पर पहुंचे। चायलों का उपचार जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी चिकित्सालय में किया जा रहा है। चर्चा है कि गोदाम में अवैध रूप से पटाखे बनाये जा रहे थे। गोदाम मालिक अशोक अठावाल ने सोनू सिंघी को गोदाम किराये पर दे रखा था और सोनू बिना लाइसेंस के पटाखे बना रहा था। आग लगने के बाद गोदाम में दो बड़े धमाके हुए और रह-रहकर पटाखों की



बांसवाड़ा में पटाखों के गोदाम में लगी आग से उठता धुआं।

गूज सुनाई देती रही। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गये जिनमें से धमाके की चपेट में आकर कुछ झुलसे गये।

गोदाम की दीवार तुड़वाई जिसके बाद मीणा स्वयं अंदर पहुंचे। गोदाम से दंपती और चार बच्चे सुरक्षित निकल गये थे। प्रत्यक्षदर्शी शाहिद मंसूरी ने बताया कि गोदाम के बाहर खड़े थे कि

अचानक धमाकों की आवाज आयी और धुआं उठने लगा। तत्काल प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और अग्निशमन को टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि गोदाम पर अक्सर

■ नौ दमकलों की मदद से लगभग दो घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका

■ चर्चा है कि गोदाम में अवैध रूप से पटाखे बनाये जा रहे थे, गोदाम मालिक ने गोदाम किराये पर दे रखा था

ताला ही लगा रहता था हाल ही में ऊंची दीवारें भी बनाई गयी थी। इधर बाद में जिला कलेक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव एवं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला चिकित्सालय पहुंचे और चायलों की कुशलक्षेम पूछी। इधर पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा, राजतालबा थानाधिकारी दिलीप सिंह चारण एवं अन्य पुलिस अधिकारी के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गायल भी मौके पर पहुंचे।

महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस खड़े ट्रक से टकराई, तीन की मौत

हादसे में दो जने गंभीर रूप से घायल हुए, उपचार के लिए कोटा भेजा

कोटा, (निर्स)। प्रयागराज महाकुंभ से मंदसौर जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक स्लीपर कोच बस दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर गुस्वार तड़के पीछे से खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के केबिन में सवार दम्पती सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए कोटा के एमबीएम अस्पताल ले जाया गया



के जरिए मंदसौर लौट रहे थे। इस हादसे में उनके सास-ससुर कैलाशी बाई और किशोरी लाल की मौत हो गई है, जिस समय घटना हुई अधिकांश लोग बस में सो ही रहे थे। इस बस में सवार अधिकांश उनके रिश्तेदार या जानकार या समाज के ही हैं।

कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत

बीकानेर, (निर्स)। बीछवाल पुलिस थाना क्षेत्र में बदरासर के पास देर रात कार की टक्कर से बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद कार का टायर फट गया जिसे छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार धरूपवा निवासी हुकुमचंद मेघवाल, पप्पूराम और किशोराराम बाइक पर सवार होकर बीकानेर से अपने गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान रात को करीब 12 बजे बदरासर के पास जीणमाता मंदिर पहुंचने वाले थे कि पीछे से आ रही कार के चालक ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हुकुमचंद और पप्पूराम की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीर की गाड़ी में किशोराराम को पीबीएम अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद कार चालक ने भगने की कोशिश की तो कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका टायर फट गया। चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कार की टक्कर से बाइक चकनाचूर हो गई। पुलिस ने दोनों गाड़ियां जब्त की हैं। हुकुमचंद के भाई गोरधन कुमार मेघवाल की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने दोनों गाड़ियों के चालक को भी पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

हादसे में बस का एक साइड का हिस्सा चकनाचूर हो गया।

कंडेक्टर साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि मौके से बस चालक फरार हो गया है। मामला दर्ज कर चालक की तलाश की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सिमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस से घायलों व मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कई यात्री बस में फंस गए थे, जिन्हें निकाला गया है। हादसे में मृतकों की पहचान मंदसौर निवासी कैलाशी बाई (64), उनके पति किशोरी लाल (65) और

मंदसौर निवासी अशोक (35) के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल चमन लाल और पार्वती को तत्काल पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। बस में मौजूद करीब एक दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं को दूसरी बस में सवार कराकर अपने अपने गंतव्य के लिये रवाना कराया। बस में सवार लोकेश पवार का कहना है कि वह मंदसौर से 56 लोग बस करके महाकुंभ में गए थे। वापसी में आगरा घूमने भी पहुंच गए थे। आगरा से रात को कोटा होते हुए एक्सप्रेस-वे

■ प्रयागराज से मंदसौर जाते समय सिमलिया के समीप हुआ हादसा, बस चालक मौके से फरार हुआ

■ जिस समय घटना हुई अधिकांश लोग बस में सो रहे थे, बस सवार अधिकांश रिश्तेदार या जानकार या समाज के ही थे

जहां पर घायलों का उपचार जारी है। तीनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखवा दिए हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शवों को रवाना किया। सभी महाकुंभ से लौट रहे थे। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि घटनाक्रम सुबह छह बजे के आसपास हुआ है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 56 यात्रियों से भरी एक स्लीपर कोच बस प्रयागराज महाकुंभ से मंदसौर के लिये रवाना हुई थी। सिमलिया थाना क्षेत्र के कराडिया के नजदीक फोर लेन पर एक ट्रक खड़ा था संभवतः बस चालक को नींद का झटका लगा जिससे तेज रफ्तार से आ रही बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की

ट्रॉली के नीचे आने से युवक की मौत

श्रीगंगानगर, (निर्स)। कालियां बस स्टैंड पर मिट्टी की भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आने से बाइक चालक युवक की मौत हो गई। हादसा शाम को करीब पांच बजे हुआ। सूचना पर सदर थाने से हैड कॉन्स्टेबल रूपराम मय जाबला मौके पर पहुंचे। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

मृतक अबोधर तहसील के पंजपीर कालोनी निवासी 25 वर्षीय संजु ओड राजपूत पुत्र श्रवण कुमार के परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस का ससुराल कालियां के निकट कालोनी में है। वह अपने ससुराल में मिलकर वापस पंजपीर के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान कालियां बस स्टैंड पर हादसा हुआ। युवक सड़क पर गिरकर सामने से आ रही मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आ गया। इससे उसका सिर कुचला गया और मौके पर ही मौत हो गई। कालियां गांव के प्रशासक पवनदीप शेरगिल ने बताया कि घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने रास्ता जाम कर लिया और आवामन बाधित हो गया। लोगों ने ट्रैक्टर के चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

दो सगे भाइयों को अनियंत्रित टैंपो ने टक्कर मारी, एक की मौत

धौलपुर, (निर्स)। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाइवे 11 जी पर बुधवार की देर शाम चिलाचौद गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। खेतों की रखवाली करने जा रहे दो सगे भाइयों को पीछे से अनियंत्रित टैंपो ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे भाई का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना के बाद आंच में जुटी हुई है।

चिलाचौद गांव निवासी 17 वर्षीय सचिन पुत्र वीर सिंह मीणा अपने छोटे भाई 15 वर्षीय सौरभ के साथ खेतों की रखवाली करने गांव से करीब दो किलोमीटर दूर खेतों पर पैदल घूमते हुए

सहायक अभियंता व बाबू 30 हजार की रिश्त लेते ट्रैप

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बनेड़ा कार्यालय में कार्यरत है सहायक अभियंता व बाबू

■ कॉर्मिशियल बिजली कनेक्शन जारी करने के एवज में रिश्त राशि एक लाख की डिमांड की

आवश्यकता थी। इसके लिए वह अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनेड़ा के सहायक अभियंता मुकेश बैरवा से मिला।

अभियंता ने कनेक्शन जारी करने के लिए एक लाख रुपये रिश्त राशि की डिमांड की थी। उदयलाल, इन्हें रिश्त नहीं देकर रंरा हाथ पकड़वाना

चाहता था। इसके चलते उसने एसीबी में शिकायत दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया। इस दौरान सहायक अभियंता ने 20 हजार रुपये प्राप्त कर लिये। 30 हजार रुपये गुस्वार को देने थे। इसके लिए उदयलाल आज राशि लेकर बनेड़ा के सहायक अभियंता मुकेश बैरवा के पास गया। अभियंता ने यह राशि निगम के ही बाबू विनोद को देने के लिए कहा। विनोद ने जैसे ही उदय लाल से राशि ली, एसीबी की टीम उदयलाल का संकेत पाकर मौके पर पहुंच उसे रंरा हाथों पकड़ लिया। एसीबी का कहना है कि फिल्हाल कारवाई जारी है।

रजिस्ट्री की नकल के एवज में 15 हजार मांगे, बाबू को पकड़ा

अलवर, (निर्स)। अलवर के बहादुरपुर सब रजिस्ट्रार के बाबू को रजिस्ट्री की नकल देने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्त लेते हुए एसीबी ने ट्रैप कर लिया। दूसरा आरोपी बाबू मौके से फरार हो गया। सहायक रजिस्ट्रार के शामिल होने की जांच होगी।

एसीबी के परमेश्वर लाल ने बताया कि परिवारी ने 11 फरवरी को सूचना दी कि मुझसे रजिस्ट्री की कॉपी लेने के एवज में बहादुरपुर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू ने 15 हजार रुपये मांगे हैं, जिसका सत्यापन सही पाया गया। इसके बाद ट्रैप की कार्यवाही की गई। गुस्वार दोपहर बाद में बहादुरपुर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू दिनेश मीणा 15 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया। दूसरा बाबू हितेंद्र मौके से फरार हो गया जिसे जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। सहायक रजिस्ट्रार भानुश्री की



आरोपी बाबू।

भूमिका की जांच होगी। हालांकि परिवारी ने उनकी मिलीभगत होने का शक जाहिर किया है। उधर, परिवारी ने बताया कि 31 जनवरी को जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। रजिस्ट्री की कॉपी लेने आया

■ दूसरा आरोपी बाबू मौके से फरार, सहायक रजिस्ट्रार के शामिल होने की जांच होगी

तो बाबू ने 15 हजार रुपये मांगे। उससे पहले उप रजिस्ट्रार ने कहा था कि आपकी रजिस्ट्रार कॉर्मिशियल में जाएगी, जिसके 68 हजार रुपये जमा कराएँ। लेकिन बाद में बाबू दिनेश व हितेंद्र ने कहा कि हम काम करा देंगे। जिसके 15 हजार रुपये देने होंगे। यह भी कहा था कि मैं 20 हजार रुपये मांग रही है लेकिन हम 15 हजार रुपये में काम कर देंगे। पैसे मांगने के बाद एसीबी को शिकायत दी। उसके बाद आरोपी को एसीबी ने ट्रैप किया है।

दिल्ली-मुम्बई रेलवे ट्रैक पर कोचिंग छात्र का शव मिला

■ हादसा या सुसाइड, पुलिस जांच में जुटी, बिहार का निवासी था छात्र

कोटा, (निर्स)। कोटा मंडल के डकनिया रेलवे स्टेशन के समीप गुस्वार रात्रि को दिल्ली-मुम्बई रेलवे लाइन पर कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे एक छात्र का शव मिला। सूचना पाकर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान बिहार निवासी हिमांशु शर्मा के रूप में हुई, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जायेगा। जीआरपी के पुलिस उपअधीक्षक

मौके से एक मोबाइल मिला। मोबाइल व पृथक्ता करने पर प्रथमदृष्टया से उसकी पहचान बिहार निवासी हिमांशु शर्मा (18) के रूप में हुई है जो कोटा के विज्ञान नगर में रहकर कोचिंग कर रहा था। पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि मृतक के पास

पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद मृतक की शिनाख्त कराई जायेगी। जांच के बाद ही स्पष्ट पता चलेगा कि कोई हादसा है या सुसाइड का मामला है।

शंकर लाल ने बताया कि डकनिया रेलवे स्टेशन के समीप एक शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक का शव क्षत-विक्षिप्त हालत में मिला। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि मृतक के पास

कार्यालय नगरपरिषद चुरू (राजस्थान)

क्रमांक : न.प./सकाई शाखा /2024-25/13445012 दिनांक :- 07.02.2025
ई-निविदा सूचना 113 वर्ष 2024-25
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से नगरपरिषद, द्वारा कार्य की निविदा आईडी नम्बर DLB2425A55534 आह्वान की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://proc.rajasthan.gov.in> पर तथा कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगरपरिषद चुरू के कार्यालय में एक सौ सूचना पर देवी कोटा का सफाई है।
UBN Code :- DLB2425SL016763, DLB2425SL016764
राज.सं.वार/सी/24/11634 आयुक्त, नगर परिषद चुरू

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर, जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर
टैलीफोन नम्बर :- 01462-330051 ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com
ऑन लाइन निविदा सूचना संख्या 13/2024-25
नगर पालिका बिजयनगर द्वारा राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेद्यता से निविदा कार्य हेतु ऑन लाइन निविदा निवारित प्रणय में ई-प्रोक्चरमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट <https://proc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। ऑन लाइन निविदा सूचना संख्या 13/2024-2025 के कार्य संख्या 01 से 44 की अनुमति लागत 1074.57 लाख है। ऑन लाइन निविदाएं दिनांक 14-02-2025 से 24-02-2025 समय सांघ 6:00 बजे तक डाउनलोड की जाकर दिनांक 25-02-2025 को निविदा शुरू, अनागत राशि एवं प्रोसेडिंग शुल्क की डी.डी. भौतिक रूप से समय 12:00 PM तक कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। ऑन लाइन निविदा की ऑन लाइन निविदा खोलने की दिनांक 27-02-2025 समय प्रातः 10:00 बजे खोली जायेगी। अधिक जानकारी वेबसाइट <https://sppp.raj.gov.in> एवं <https://proc.rajasthan.gov.in> पर देवी कोटा का सफाई है।
UNB Reference No.:- DLB2425A55556 राज.सं.वार/सी/24/11619 अधिशासी अधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक निदेश/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 02)/2025/ई-10075
ई-नीलामी विद्यार्थी संख्या-ERCC/RCC 02/2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्यान खनिज रियायत निगमवाली 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विद्यार्थी से अध्यान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों/बनार लाइसेंसों व परमित क्षेत्रों से निर्मित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, परमित शुल्क, भ्रिमीयम शुल्क, डी.एम्.एफ.टी., आर.एस.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 27 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अनागत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है। (सम्बन्धी प्रस्ताव)MS DIPP/C1575/2025 निदेशक

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक-संश्लेष वि. सं.25/परिष्कार/लेखपत्र-आयुक्ता/SP/CEP-1/2024-25/215-219 दिनांक- 13.02.2025
आयोग द्वारा आयुक्ता व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाओं हेतु आबंदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सहायक सेवा नियमों का अनुसूची आवधिक सेवा के तहत है। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का आवधिक आयोग की वेबसाइट <https://psp.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देश/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के अधिकारी से निविदा स्थापन करके व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त दूर व्यवहार सहित, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।
राम निवास मेहता, सचिव

झुंझुनू की जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ैला ने 1830 पीएचडी डिग्री बांटी, यूजीसी ने सवाल उठाए

झुंझुनू, (निर्स)। जिले के बिसाऊ रोड पर स्थित चुड़ैला में संचालित जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबडवाला (जेजेटी) विश्वविद्यालय का बड़ा फर्जीबाड़ा सामने आया है। जानकारी के अनुसार जेजेटी यूनिवर्सिटी ने पीएचडी डिग्रीयों में बड़ा फर्जीबाड़ा किया है। जिसके चलते यूजीसी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अब यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्सेज में आगामी पांच सालों के लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संदर्भ में यूजीसी ने बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी को लेकर शिकायतें दो थी कि उनके द्वारा यूजीसी के मापदंडों के विपरित जांच पीएचडी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और डिग्री बांटी जा रही है। जब यूजीसी ने मार्च-अप्रैल 2024 से जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबडवाला विश्वविद्यालय चुड़ैला द्वारा 2016 से 2020 तक दरमियायन दी गई पीएचडी डिग्रीयों की जांच शुरू की तो चौंकाने

■ पीएचडी नहीं करवा सकेगी जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ैला, पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया

■ यूजीसी ने जेजेटी यूनिवर्सिटी को 23 अक्टूबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा था

वाले खुलासे हुए जांच में यूजीसी की गठित टीम द्वारा विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्ड, एक्सपर्ट मेम्बर, पर्यवेक्षक, परीक्षक आदि के नाम-पते गायब मिले। वहीं ऐसी कई खामियां मिली, जिसमें यूजीसी के दिशा निर्देश, नियम आदि की पालना नहीं की गई। खामियों को लेकर यूनिवर्सिटी के साथ यूजीसी की तीन-चार बार बैठकें भी हुईं, जिसमें भी यूनिवर्सिटी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाई। जिसके बाद अब यूजीसी ने पांच साल के लिए पीएचडी कोर्सेज में प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। निवासी कैलाशी बाई (64), उनके पति किशोरी लाल (65) और

2016 से 2020 तक 1830 डिग्री बांटी :- यूजीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 2016 से 2020 तक पीएचडी डिग्री की जांच की गई तो यूनिवर्सिटी ने 1830 डिग्री का रिपोर्ट दिया। इनमें से 2020 में 408 डिग्री शामिल हैं, जिसे यूजीसी ने सामान्य संख्या से कई ज्यादा माना। इन पांच सालों का रिपोर्ट देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2021 से 2025 तक भी करीब करीब दो हजार डिग्री यूनिवर्सिटी ने बांटी होगी। इस तरह करीब 3800 से 4000 स्कॉलर्स की पीएचडी डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। 23 अक्टूबर को दिया था कारण बताओ नोटिस :- यूजीसी ने जेजेटी यूनिवर्सिटी को 23 अक्टूबर

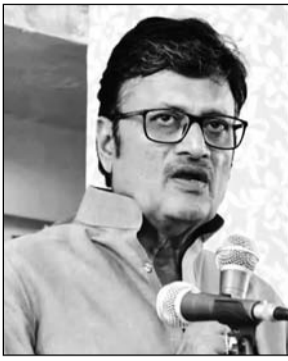
2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें 15 दिन का समय देते हुए 10 बिन्दुओं पर यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया। लेकिन यूजीसी जवाब से असंतुष्ट दिखी। इसी रिपोर्ट में यूजीसी ने बताया कि 2016 से 2020 तक जेजेटी यूनिवर्सिटी ने 1830 पीएचडी डिग्री बांटी। इनमें 408 डिग्री अकेले 2020 में बांटी गई। यह संख्या सामान्य से अधिक पाई गई। विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्डों में अनियमितताएं, पाई गई। एक्सपर्ट मेम्बर के नाम और डिग्री शामिल हैं, जिसे यूजीसी ने सामान्य संख्या से कई ज्यादा माना। इन पांच सालों का रिपोर्ट देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2021 से 2025 तक भी करीब करीब दो हजार डिग्री यूनिवर्सिटी ने बांटी होगी। इस तरह करीब 3800 से 4000 स्कॉलर्स की पीएचडी डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। 23 अक्टूबर को दिया था कारण बताओ नोटिस :- यूजीसी ने जेजेटी यूनिवर्सिटी को 23 अक्टूबर

किया, जो यूनिवर्सिटी का नहीं था, रिसर्च भी अन्य कॉलेजों से किए जाना दिखाया गया। यह सब नियम विरुद्ध था। जो भी पर्यवेक्षक थे, जो जेजेटी के टीचर नहीं थे। छह माहों रिपोर्ट में विद्यार्थियों के साइन तक नहीं मिले। डॉ. देवेन्द्रसिंह बुल, प्रेजीडेंट, जेजेटी यूनिवर्सिटी, चुड़ैला, झुंझुनू ने बताया कि यूजीसी ने हमें गुणवत्ता के लिहाज से कुछ निर्देश दिए हैं। लगातार सुधार किए जा रहे हैं। फिल्हाल पीएचडी एडमिशन पर प्रतिबंध है, लेकिन हम यूजीसी से अपील करेंगे, दुबारा एडमिशन लिए जा सकेंगे। फर्जी डिग्री को लेकर ना तो यूजीसी के पास पहले कोई शिकायत थी और ना अब है। सभी कार्यक्रम और सभी कोर्स यूजीसी के निर्देशों के अनुसार ही चल रहे हैं, जहां अधिक पैर का एक घुटना को लेकर, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी लगातार अपना पक्ष यूजीसी के समक्ष रखेगी। हमने अब तक जो भी पीएचडी कोर्स करवाए हैं। वो पूरे नियमों में करवाए हैं।

गहलोटजी बेहतर जानते हैं, फोन टैप कैसे होते हैं : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोट का टेलीफोन टैपिंग पर बयान और वर्तमान सरकार पर निशाना, ऐसा लगता है कि 'नौ नौ चूहे खा के बिल्ली हज्र को चली'।

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि गहलोट साहब टेलीफोन टैप कैसे होते हैं, सरकार क्या पद्धत रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोकेश शर्मा 5 वर्ष तक आपके ओएसडी रहे। दोनों के बीच फोन टैपिंग से संबंधित बातचीत का ऑडियो आज भी मीडिया के पास है। उस ऑडियो में वह इस्ट्रूट नष्ट करने



राजेन्द्र राठौड़

की बात कह रहे हैं।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि

■ 'कोर्ट में दिया ओएसडी का बयान क्यों भूल रहे गहलोट'

गहलोट का ओएसडी कोर्ट में इकबालिया बयान देता है कि आपके निर्देश पर कई नेताओं के टेलीफोन टैप हुए। यह 'उल्टे बांस बरेली को' क्यों। यह सारी बात जनता समझती है।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा में सदन के नेता के बोलने पर विरोध कर रहे थे, सदन की गरिमा गिरा रहे थे। उसमें से आधे

से ज्यादा कांग्रेसी विधायक यह कहकर बाहर निकल गए कि दलित समाज से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और वे कांग्रेस पार्टी की बात से सहमत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़ों-टुकड़ों में बटी है। यह पार्टी पांच सितारा होटलों में कैद रही, आज इनके पास मुद्रा नहीं है, कांग्रेस मुद्राबिहीन हो चुकी है। यह चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह राजस्थान की जनता है सब जानती है। इनकी कलाई पूर्व में खुल चुकी है। अच्छा रहता ये अगर अपने ओएसडी से बात कर लेते।

एयर फोर्स स्टेशन जयपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया

जयपुर। एयर फोर्स स्टेशन जयपुर द्वारा 10 से 13 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवधि में यातायात नियमों की जागरूकता, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण, वाकथॉन, निजी वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच जैसी पहल शामिल रही।

सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन आज एयर फोर्स स्टेशन जयपुर-जल महल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन एवं स्टेशन मास्टर विनय भारद्वाज की उपस्थिति रही।

समारोह के दौरान परिवहन निरीक्षक (आरटीओ) दिनेश सिंह फौजदार ने लाइसेंस रणनीति और सड़क दुर्घटनाओं के घातक कारणों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके अलावा, मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी की डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स नेहा खल्लर ने सड़क सुरक्षा कानून और मोटर वाहन ड्राइविंग नियमों पर व्याख्यान दिया, जबकि मुस्कान फाउंडेशन के प्रशिक्षक समीर नैवाल ने यातायात संकेतों (साइजिन) की महत्ता पर जागरूकता बढ़ाई। इस व्याख्यान में एयर फोर्स स्टेशन के अधिकारियों एवं



सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन गुरूवार को एयर फोर्स स्टेशन जयपुर-जल महल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन एवं स्टेशन मास्टर विनय भारद्वाज की उपस्थिति रही।

कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, एयर फोर्स स्कूल के छात्रों को सड़क सुरक्षा पर पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समापन समारोह में सभी उपस्थित लोगों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली, जिसमें उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

सी.एस. बताए मुकदमों के प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत में लंबित अधिकांश मामलों के प्रभारी अधिकारी पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी लापरवाही से अदालत को मामले की सुनवाई टालनी पड़ती है। प्रभारी अधिकारी कई मामलों में न तो संबंधित दस्तावेज सरकारी वकीलों को उपलब्ध करा रहे हैं और ना ही तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करते हैं। जिसके कारण सरकारी वकीलों को भी अदालत से समय मांगना पड़ता है। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वह शपथ पत्र पेश कर बताए कि इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है। अदालत ने मुख्य सचिव को यह भी आदेश दिए हैं कि वह सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि कर्मचारियों पर की जाने

■ हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत में लंबित अधिकांश मामलों के प्रभारी अधिकारी पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी लापरवाही से अदालत को मामले की सुनवाई टालनी पड़ती है।

वाली विभागीय कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह आदेश सरदार मल यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने महाधिवक्ता और प्रमुख विधि सचिव को भी कहा है कि वे विभागों के मुखियाओं को निर्देश दें कि वे विधि अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहे। अदालत ने प्रभारी अधिकारियों को चेताया है कि यदि अब उनके

सहयोग के अभाव में कोर्ट सरकार के खिलाफ आदेश देगी तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की होगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।

अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता को नवंबर, 2011 में चार्जशीट दी गई और मार्च, 2014 में जांच पूरी होकर रिपोर्ट भी सौंप दी गई, लेकिन यह बड़े आक्षेपों का बावजूद कि करीब 12 साल बीतने पर भी अब तक उस पर कोई

अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके लिए याचिकाकर्ता को अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी और गत 31 जनवरी को वह रिटायर भी हो गया। जबकि सिविल सेवा नियम के तहत जांच रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद उस पर अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रयास करना चाहिए कि वह कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच छह माह में पूरी करे। राज्य सरकार के खिलाफ अधिकांश मुकदमें दायर होते हैं। ऐसे में प्रभारी अधिकारियों की जवाबदेही बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रभारी अधिकारी को निष्क्रिय रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी विभाग में काम अधिक है तो अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी लगाए जा सकते हैं।

देवनानी से कानपुर के संत पीठाधीश्वर ने की मुलाकात



जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कानपुर के श्री नित्येश्वर आश्रम (उदासीन) के संत पीठाधीश्वर ने गुरूवार को विधान सभा में मुलाकात कर महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले श्री नित्येश्वर महादेव के महारूपाभिषेक और विशाल भंडारा का निमंत्रण दिया। देवनानी ने संत श्री पीठाधीश्वर को सनतनी परम्परा के महापर्व पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दीं।

देवनानी को संत पीठाधीश्वर ने श्री नित्येश्वर ज्ञान गंगा की प्रति भेंट की। देवनानी को बताया कि पुस्तक में सनतन परम्परा और आध्यात्म विषयों से संबंधित तपस्या, वैराग्य, साधना, परमात्मा, वास्तविक शांति, पूजा, भक्ति, अराधना, पाप, पुण्य सहित आस्था और विश्वास से संबंधित आमजन के सामान्य प्रश्नों का सरलता से जवाब दिया गया है।

वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति पर लगी रोक हटी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर से वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति पर अप्रैल, 2023 में लगी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन विभाग में देने को कहा है। वहीं विभाग को इन अभ्यावेदन का दो सप्ताह में तय करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभ्यावेदन के निस्तारण तक याचिकाकर्ताओं के मामले में यथास्थिति रहेगी। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह आदेश गजेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को निस्तारण करते हुए दिए। अदालत आदेश से 5168 कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि 2 दिसंबर, 2019 को वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं का भी नाम था। वहीं बाद में वरिष्ठता में नहीं आने के चलते उनकी पदोन्नति नहीं हुई। याचिका में कहा गया कि विभाग ने साल 2013 से 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध 23 जनवरी, 2023 को रिज्यू डीमांड किया। वहीं वरिष्ठता सूची बनाते समय आरक्षित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव के निलंबन पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव पद से याचिकाकर्ता को निलंबित करने के आदेश को क्रियान्वित पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कर्पूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दो बार एसोसिएशन की ओर से गत 27 जनवरी को पत्र भेजकर जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उनकी ओर से किया गया व्यवहार घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

सुखोई के साथ राजीव प्रताप रूडी ने फिर भरी हौसलों की उड़ान



पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरते हुए अपनी उड़ान क्षमता और साहस का प्रदर्शन किया।

बेंगलुरु/जयपुर। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरते हुए अपनी उड़ान क्षमता और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने 12 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2025 एयर शो में 22,000 फीट की ऊँचाई पर 52 मिनट तक शानदार कलाबाजियों की।

रूडी ने उड़ान के अनुभव को रोमांचक बताते हुए कहा कि "सुखोई-30 एमकेआई उड़ान एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। वाणिज्यिक पायलट के रूप में उड़ान भरने की आदत है, लेकिन इस उड़ान विमान को उड़ाना पूरी तरह से शक्ति, गति और सहनशक्ति की परीक्षा थी।" विंग कमांडर परमिंदर चहल (पैर) के साथ उन्होंने टम्बल, लूप, बैरल रोल जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले युद्धाभ्यास किए। उड़ान से पहले उन्होंने जी-सूट पहनकर सभी शारीरिक फिटनेस परीक्षण पूरे किए। एयर शो के दौरान रूडी ने भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों एसयू-35 तथा सुखोई-57 का प्रदर्शन भी देखा। साथ ही, उन्होंने

- एयरो इंडिया 2025 एयर शो, बेंगलुरु में 22,000 फीट की ऊँचाई पर 52 मिनट तक उड़ान
- विंग कमांडर परमिंदर चहल के साथ टम्बल, लूप, बैरल रोल जैसे युद्धाभ्यास किए

भारतीय वायुसेना की विख्यात एरोबैटिक प्रदर्शन टीम 'सूर्य किरण' के शानदार हवाई करतबों को करीब से देखा। रूडी ने भारतीय वायुसेना के पायलटों की कुशलता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा, "भारतीय वायुसेना की ताकत और परिश्रम को सलाम। इनके रहते हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। रूडी ने कहा कि सूर्य किरण टीम को बिहार में आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि यह भारतीय वायुसेना की प्रमुख एरोबैटिक टीम है, जो अपने अद्वितीय हवाई कौशल और सटीक उड़ान प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। सूर्य किरण टीम कर्नाटक के बीदर एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित है और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एयर शो में कई शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। बिहार में इसके आगमन से युवा पीढ़ी को भारतीय वायुसेना के शौर्य और तकनीकी

उत्कृष्टता को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी एक लाइसेंससुद्धा वाणिज्यिक पायलट हैं और पूर्व में भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। यह उनकी दूसरी सुखोई उड़ान थी, इससे पहले 2015 में भी वे सुखोई एमकेआई 30 में उड़ान भर चुके हैं। मालूम हो कि सुखोई लड़ाकू विमान 2600 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होने वाला पहला लड़ाकू विमान सुखोई है जिसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है।

गौरतलब है कि रूडी एक लाइसेंससुद्धा वाणिज्यिक पायलट हैं और पूर्व में भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। यह उनकी दूसरी सुखोई उड़ान थी।

समस्त गतिविधियों की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करें : मंजू राजपाल

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष एवं 'सहकार से समृद्धि' की समीक्षा बैठक

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों मंजू राजपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 एवं 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों की समयावधि क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 'सहकार से समृद्धि' के इनिशिएटिव के आधारे पर जिलों की रैंकिंग तय करने एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार

कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। राजपाल गुरूवार को नेहरू सहकार भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष एवं 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीं। बैठक में मेक्स कम्प्यूटराइजेशन, एम-पैक्स एवं ई-पैक्स का गठन, निष्क्रिय समितियों का अवसथान, फार्मर रजिस्ट्री कैम्प के अंतर्गत होने वाले कार्य, गोदाम निर्माण, जन औषधि केन्द्र, पीएम किसान समृद्धि कैम्प,

एफपीओ एवं कॉमन सर्विस सेंटर सहित विभिन्न विन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि जिन जिलों में डीसीडीसी (जिला सहकारी विकास समिति) की बैठक नहीं हुई है, उनमें एक सप्ताह के अंदर बैठक आयोजित करवाकर प्लान स्वीकृत करवाया जाए, ताकि कार्ययोजना को समयबद्ध रूप से मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होंने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने

के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें सहयोग नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती राजपाल ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके राजसमन्द जिले की सराहना करते हुए अन्य जिलों को भी इसका अनुसरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) को इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने एवं बेहतर कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों को केरल सरकार के साथ साझा किया

मदन दिलावर ने इंस्टिट्यूट ऑफ़ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ली बैठक

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग के शैक्षणिक दौरे पर राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल केरल पहुंचा। केरल इंस्टिट्यूट ऑफ़ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, त्रिचूर में आयोजित बैठक में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में पंचायती राज विभाग

ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य आगामी दो वर्षों में प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के मामले में देश में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह प्रतिदिन सफाई और कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। दिलावर ने राजस्थान में संचालित

अन्नपूर्णा रसोई, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, घुमंतू जाति के लोगों को पढ़ा वितरण योजना, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर जानकारी दी। साथ ही इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पिछले वर्ष करावाएंगे प्रशिक्षणों एवं राज्य स्तरीय 6 प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों के बारे में बताया।

इससे पहले केरल राज्य में पंचायती राज के नवाचार तथा सशक्त पंचायती राज के बारे में वहां के अधिकारियों, प्रोफेसर, ट्रेनिंग इंचार्ज, फैकल्टी मेंबर्स के साथ जानकारी को साझा किया। अधिकारियों द्वारा केरल राज्य में पंचायती राज सिस्टम के बारे में एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

उपभोक्ताओं को सुगमता से मिले बिजली संबंधी सेवाएं : आरती डोगरा

जयपुर। विद्युत वितरण निगमों की अध्यक्ष आरती डोगरा ने निचले स्तर तक निगम की उपभोक्ता सेवाओं को सुगम एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने, लोड बढ़ाने, बिजली बिल में सुधार तथा निबंध बिजली आपूर्ति जैसी आमजन से जुड़ी सेवाओं में कोई कोताही नहीं हो। पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।

डिस्कॉन्स चेरमैन के गुरूवार को चाकसू, निवाड़ी, टॉक ए-प्रथम तथा हिंडोली एड्डेन कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में अभियंताओं को

यह निर्देश दिए। डोगरा ने संबंधित 33/11 केवी गिड सब स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रबी सीजन के अंतिम चरण तथा आगामी गर्मी में बिजली की संभावित डिमांड को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, केबल, रॉटर स्विच, आइसोलेटर, वॉसी ब्रेकर जैसे लाइन मैटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, ट्रिपिंग की समस्या वाले फीडरों में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने को कहा।

डोगरा ने इस दौरान एड्डेन कार्यालयों में भंडार शाखा, उपभोक्ता शाखा, राजस्व एवं बिलिंग तथा संस्थान शाखाओं से संबंधित कार्य

का निरीक्षण किया। उन्होंने सहायक अभियंताओं एवं अन्य कार्मिकों से संबंधित कनेक्शन आवेदनों की संख्या, निस्तारण में लगने वाले समय, भार वृद्धि के प्रकरणों, शत-प्रतिशत बिलिंग, डिफेक्टिव मीटर बदलने, बकाया राजस्व की वेस्यूली आदि के संबंध में जानकारी ली और दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम सूर्यचर निशुल्क बिजली योजना के तहत स्थापित रूफ टॉप सोलर की संख्या के बारे में भी जानकारी ली और इसे गति प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे।

जवाहर कला केंद्र में मांड गायन कार्यशाला 20 से

जयपुर। जवाहर कला केंद्र की ओर से 20 फरवरी से 6 मार्च तक 15 दिवसीय मांड गायन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागियों को प्रसिद्ध मांड गायक पद्मश्री अलंकृत उस्ताद डॉ. अली मोहम्मद और उस्ताद डॉ. गनी मोहम्मद के सानिध्य में मांड गायकी सीखने का अवसर मिलेगा। पारिजात-2 दीर्घा में सायं 3 बजे से 6 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी केंद्र की वेबसाइट पर मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए अनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी कार्यशाला में निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गयी है।

बीछवाल जलाशय में आने वाली कंवरसेन नहर में जेट फ्यूल से भरा टैंकर गिरा

12 हजार लीटर तेल पानी में बहा, जलदाय विभाग ने पानी बंद किया

लूणकरणसर, (निसं)। हंसेरा के पास कंवरसेन नहर में 28 हजार लीटर जेट फ्यूल से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। नहर में इन दिनों केवल बीकानेर के बीछवाल जलाशय में पानी का पानी देने के लिए दो से तीन फीट का पानी ही चल रहा था। नहर में टैंकर के गिरकर पलटो खा जाने से उसके अंदर से जेट फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। घटना के करीब एक से सवा घंटे के बाद इसकी सूचना नहर विभाग और जलदाय विभाग को मिली। इसके बाद नहर विभाग ने हंसेरा के पीछे से आ रहे पानी को रोक दिया। वहीं जलदाय विभाग ने इस पानी को पेयजल स्रोतों में लेने से मना कर दिया। बीकानेर में भी जलदाय विभाग ने बीछवाल जलाशय में नहर के पानी को लेने से पहले उसके सैंपल लेने के आदेश दिए। अब हर छह घंटे से जलदाय विभाग बीछवाल जलाशय में आने वाले पानी के सैंपल ले रहा है। सैंपल पास होने के बाद ही नहर से बीछवाल जलाशय में पानी छोड़ा जाएगा।



बीछवाल जलाशय में आने वाली कंवरसेन नहर में गिरा टैंकर।

ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी कि हंसेरा के पास कंवरसेन नहर में एक टैंकर गिर गया है। तत्काल हम मौके पर पहुंचे तो नहर में गिरे टैंकर में तीन जने फंसे हुए थे। इसमें हरियाणा निवासी ड्राइवर कमल चमकार, कैथल निवासी अनिल चमार और मनदीप थे। तीनों को बाहर निकालकर बीकानेर के ट्रामा

सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वे पंजाब से टैंकर में जेट फ्यूल लेकर नाल एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। हंसेरा पुलिस के पास उनका टुक अनियंत्रित होकर पलट गया। टुक को बाहर निकालने के लिए पूरे दिन प्रयास करते रहे। रात नौ बजे बाद टैंकर को बाहर निकाला गया। नहर में करीब 12 हजार

■ अब हर छह घंटे से जलदाय विभाग बीछवाल जलाशय में आने वाले पानी के सैंपल ले रहा है, सैंपल पास होने के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा

लीटर फ्यूल बहा गया। फ्यूल को बाहर निकालने के लिए दो मोटर पंप लगाए गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

नहर विभाग के एक्सईएन संदीप भाटी ने बताया कि नहर में फ्यूल टैंकर गिरने की सूचना मिलते ही हमने पीछे से आ रहे पानी को आरडी 303 पर ही बंद कर दिया। जलदाय विभाग को भी इसकी सूचना दे दी। नहर के जिस पानी में तेल मिल गया है, उसे गुरवार सुबह बीकानेर से पहले रिजर्व जलाशयों में डाला जाएगा। तब तक कंवरसेन नहर में पानी नहीं छोड़ा

जाएगा। फ्यूल टैंक निकलने के बाद नहर में तेल की जांच करने के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा।

वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के एईएन भरत तंवर ने बताया कि प्रशासन व नहर विभाग से जानकारी मिलते ही 303 आरडी से बीकानेर की तरफ वाली सभी पेयजल स्कीमों में पानी बंद कर दिया। फ्यूल मिले होने की आशंका के चलते पानी को नहर में ही चलाया जा रहा है। किसी भी पेयजल स्कीम में यह पानी नहीं लिया गया।

राजेश राजपुरोहित, एडिशनल चीफ इंजीनियर, जलदाय विभाग का कहना है कि नहर विभाग ने बीकानेर शहर का पानी टैंकर गिरने की सूचना मिलते ही बंद कर दिया। हमने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पेयजल स्कीम में पानी लेने से पहले उसके सैंपल लिए जाए। बीछवाल जलाशय में आने वाले हर पानी की छह-छह घंटे से सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल पास होने के बाद ही पानी को जलाशय में छोड़ा जा रहा है। फ्यूल से भरे पानी को जनता तक नहीं पहुंचने देंगे।

निरीक्षण में चिकित्सा अधिकारी और कार्मिक मौके से नदारद मिले

करीली, (निसं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आमजन का समयानुरूप पहुंच की जानकारी हेतु सीएमएचओ डॉ. दिनेशचंद्र मीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासलपुर का औचक निरीक्षण किया, जहां चिकित्सा अधिकारी और कार्मिक मौके पर नदारद पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. दिनेशचंद्र मीना ने संस्था पर गतिविधियों की स्थिति जांची, जहां व्यवस्थाएं असंतोषजनक पाई गईं, जिन्हें व्यवस्थित कराने के निर्देश प्रदान किये। सीएमएचओ ने उपस्थित पंजिका का अवलोकन कर कार्मिकों की

■ नदारद पाए गए चिकित्सा अधिकारी और कार्मिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे

■ सीएमएचओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासलपुर का औचक निरीक्षण किया

मौजूदगी जांची, जिसमें उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर होने के बाद में कार्मिक मौजूद नहीं पाए गए।

उन्होंने गायकनोर्लाजिस्ट को संस्था पर डिलीवरी बढ़ाने सहित सोनोप्राफी सेवाएं प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने संस्था पर एक्स-रे मशीन के खराब जाए पाए जाने पर केपीटीएल प्रभारी से बात की और जल्द ही सुचारू

संचालन की अपेक्षा जताई। उन्होंने संस्था प्रभारी को सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देशित कर चिकित्सा अधिकारियों व कार्मिकों को निर्धारित समय तक ठहराव के लिए पाबंद करने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय तक सेवा प्रदाता कक्षां पर ताले नहीं लगाए जाएं तथा किसी जरूरी काम से

मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अन्य कार्मिक को सेवाओं के लिए पाबंद किया जाए जिससे मरीज को परेशानी न झेलनी पड़े।

इस दौरान आरसीएचओ डॉ. राजेश कुमार ने संस्था पर टीकाकरण सेवाओं का जायजा लिया। इसी क्रम में एमसीएचएन सत्र आयोजन की स्थिति की जांच जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी केंद्र भीम नगर वार्ड नंबर 33 पर की गई, जहां एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सत्र दौरान टीकाकरण करना पाया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक-आईईसी लखन सिंह लोधा मौजूद रहे।

डिवाइडर पर चढ़ी कार, एक महिला घायल

पावटा, (निसं)। भाबर थाना क्षेत्र के खालोलाई पुलिस के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत यह रही कि घटना में कार में सवार चार महिला व दो पुरुष एवं दो बच्चे थे जिनमें एक महिला सुमन शर्मा घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने भाबर थाना पुलिस को सूचित किया, जहां पुलिसकर्मीयों ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को शाहपुरा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया चिकित्सकों ने घायल महिला का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी। हादसा भाबर थाना क्षेत्र के खालोलाई पुलिस के पास सुबह करीब 8:30 पर हुआ। जब कार सवार, खाटूरस्थान के दर्शन के लिए पल्लव स्थित अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वह नेशनल हाईवे 48 भाबर खालोलाई पुलिस के पास पहुंचे तभी आगे जा रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ क्षतिग्रस्त हो गई।

निजी बस ने बाइक सवार डेयरी संचालक को कुचला, मौत



बस के नीचे फंसकर बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई

नोखा, (निसं)। बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रहे बाइक सवार डेयरी संचालक को निजी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बस के नीचे आने से बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में युवक की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे नोखा में रोड़ा रोड स्थित गोदारा पेट्रोल पंप के पास हुई।

नोखा एसएचओ अमित स्वामी ने बताया कि राजेश भट्ट (38) दोपहर को अपने गांव रोड़ा से करीब चार किलोमीटर दूर नोखा आया था। बाजार से सब्जी खरीदने के बाद वह घर लौट

■ बाजार से सब्जी खरीदकर वापस घर लौटते समय हादसा हुआ

रहा था। इस दौरान गोदारा पेट्रोल पंप के पास सवारियों से भरी एक निजी बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बस के नीचे फंसकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक भी बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन की मदद से घायल को नोखा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

एसआई राधेश्याम थालोड़ ने बताया-पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमॉर्टम की कार्यवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। राजेश भट्ट गांव में डेयरी का संचालन करता था। वह शादीशुदा था और दो बच्चे हैं।

114 किलो डोडा-पोस्त जब्त, तीन गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेंज डीआईजी ओमप्रकाश के दिशा निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशों पर जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों तस्करी व तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पीसांग थाना पुलिस के हथिये तस्करी चढ़ गए। पुलिस ने झोंपड़ी में छुपाकर रखा 114 किलो मादक पदार्थ डोडा-पोस्त बरामद कर जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी से तीन बाइक भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।

पीसांग थाना पुलिस के अनुसार ग्राम धुवाडिया में दयालराम गुर्जर के घर के पास छत्परनुमा झोंपड़ी में छपा मारकर प्लास्टिक के सात कट्टों 114 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों

टैंकर ने बाइक को टक्कर मारी, एक की मौत

निवाई, (निसं)। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राजकीय महाविद्यालय के समीप एक टैंकर ने बाइक के टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी सूरजमल जाट ने बताया गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे गांव नला निवासी रामस्वरूप चौधरी (58) पुत्र रामचन्द्र चौधरी बाइक से अपने गांव नला जा रहा था। इसी दौरान राजकीय महाविद्यालय के समीप टैंकर ने बाइक के टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय की मुर्दाघर में रखवाया और पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का बड़ा पुत्र अशोक चौधरी निवाई थाने में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है।

छह लाख हड़पने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने करीब 6 लाख रुपये हड़पने के आरोपी मार्बल व्यापारी व डलाल के खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी महेश काबरा ने एडवोकेट रमेश शर्मा व मुकेश शर्मा के जरिये अदालत की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई कि मंजिला रोड निवासी दलाल राजेंद्र गोस्वामी ने पिछले दिनों मेरी मार्बल फर्म से बालाजी मार्बल एंड ग्रेनाइट को 7 लाख 6 हजार रुपये का मार्बल व ग्रेनाइट बतौर उधार दिलाया था।

इस राशि में से एक लाख रुपये का भुगतान कर दिया, जबकि 6 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। निरंतर तकाजा किये जाने के बावजूद तामटोल रवैया अपनाकर परेशान किया जा रहा है। आधिकारिक भुगतान नहीं मिलने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर कार्यवाही की फरियाद की।

तीसरी महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आज

जोधपुर, (कासं)। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों के अतिरिक्त यातायात के मद्देनजर रेलवे द्वारा प्रारंभ की गई बाड़मेर-बरीली महाकुंभ मेला स्पेशल तीसरे ट्रिप के लिए शुक्रवार को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी।

उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे द्वारा प्रयागराज महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत ट्रेन 04811 बाड़मेर-बरीली महाकुंभ मेला स्पेशल तीसरे ट्रिप के लिए शुक्रवार शाम 5.30 बजे बाड़मेर से प्रस्थान कर रात्रि 9.20 बजे जोधपुर आकर 9.30 बजे प्रस्थान तथा प्रयागराज स्टेशन पर शनिवार शाम 7.05 बजे आगमन व 7.10 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 9 बजे बरीली पहुंच करेंगी। वापसी में ट्रेन 04812 बरीली-बाड़मेर महाकुंभ

स्पेशल ट्रेन 16 फरवरी को बरीली से रात्रि 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.15 बजे प्रयागराज आकर 11.20 बजे प्रस्थान व तीसरे दिन सुबह 8.45 बजे जोधपुर आकर 8.55 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे बाड़मेर पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्री सुविधा हेतु 2 सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी, 11 सेकंड क्लास स्लीपर, 4 जनरल व दो गार्ड के डिब्बे होंगे।

ट्रेन इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव :-सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आगमन में बालोतरा, समदड़ी, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकाना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, आगरा फोर्ट, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आगरा, दानापुर, बाटलीपुत्र व हाजीपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ट्रैक्टर ने रोडवेज बस को टक्कर मारी

अजमेर, (कासं)। अजमेर की घृघरा घाटी पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने आगे चल रही रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस चालक के सिर में मामूली चोट आई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रोडवेज बस चालक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि व्यापार डिपो की बस ब्यावर से जयपुर जा रही थी। बस में 50 यात्री सवार थे। घृघरा घाटी में बस के आगे एक एंबुलेंस चल रही थी, जिसने अचानक ब्रेक लगा दिए। बस चालक ने समय रहते बस को नियंत्रित कर लिया, लेकिन पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

डिस्कॉम से सेवानिवृत्त एक्सईएन को डिजिटल अरेस्ट कर 60 लाख की ठगी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर डिस्कॉम से सेवानिवृत्त एक्सईएन को शांति में फ्रॉड केस में डिजिटल अरेस्ट कर 60 लाख रूपयों की ठगी कर ली। घर में अकेले रहने वाले चूड़ एक्सईएन ने कल किसी परिजन के आने पर घटनाक्रम बताया और पुलिस की शरण में पहुंचे। इस बारे में सरदादापुरा पुलिस ने अग्रिम जांच आरंभ की है। मामला सामने के आने के बाद पुलिस ने बैंकों से संपर्क कर कुछ रूपयों को होल्ड भी करवाया है।

थानाधिकारी शेषकरण बारहट ने बताया कि सरदादापुरा नेहरू पार्क क्षेत्र में रहने वाले आरएएसईबी से सेवानिवृत्त एक्सईएन अजीतराज भंडारी की तरफ

■ सरदादापुरा पुलिस ने अग्रिम जांच आरंभ की, मामला सामने के आने के बाद पुलिस ने बैंकों से संपर्क कर कुछ रूपयों को होल्ड भी करवाया है

■ अजीतराज द्वारा आरजीटीएस के माध्यम से उनके खातों में अलग-अलग किशतों में 60 लाख रूपए डाले

■ पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया

से रिपोर्ट दी गई है। इनके अनुसार उनकी आयु 85 साल है। वे यहां पर जोधपुर में अकेले रहते हैं और परिवार के सदस्य बेटा-बहू इत्यादि ब्यावर व दिल्ली में रहते हैं। 2 फरवरी को उनके मोबाइल

पुलिस अधिकारी बोल रहा है और खातों में जमा रूपयों की जानकारी जुटाने की बात कहता है। 3 से 10 फरवरी तक शांति उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखते हैं वे उन्हें बताए अनुसार खातों में रूपए ट्रांसफर करने को कहते हैं। अजीतराज द्वारा आरजीटीएस के माध्यम से उनके खातों में अलग अलग किशतों में 60 लाख रूपए डाल देते हैं।

गुरुवार को परिवार का सदस्य जब उनसे मिलने आया है तो उन्होंने इस बारे में बताया। तब उनके साथ हुए फ्रॉड का पता लगाता है। इस पर अजीतराज सरदादापुरा थाने पहुंचे और शांति के खिलाफ 60 लाख की धोखाधड़ी किए जाने का केस दर्ज करवाया।

दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने का भय दिखाकर नर्सिंगकर्मी से ब्लैकमेलिंग

ब्लैकमेल करने वाले ने आरोप लगाया कि उसने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है

जोधपुर, (कासं)। जिले के ओसियां थाने में एक नर्सिंग अधिकारी ने अपने खिलाफ ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि एक जने द्वारा उसे किसी मामले में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल कर रुपए मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर नर्सिंग अधिकारी की ओर से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। इसके बाद मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामलेला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है।

ग्रामीण पुलिस को दिए परिवाद में एक नर्सिंगकर्मी ने बताया कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है। गत 29 जनवरी को उसके पास एक व्यक्ति का फोन आया और उसने आरोप लगाया कि उसने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है। जब उसने मना कर दिया तो उस पर फोन करने वाले व्यक्ति ने उस पर जोधपुर जकरम मिलने के लिए दबाव बनाया अन्यथा सामाजिक बदनामी करने की धमकी भी दी। इसके बाद एक फरवरी को आरोपी चेराई आया

■ आरोपियों के नहीं मानने पर अब परेशान होकर पीड़ित की ओर से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को परिवाद दिया गया है

■ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

और उसके अस्पताल में आकर उसे अपने साथ चलने को कहा। उसके कहने पर वह अस्पताल से बाहर आया तो एक गाड़ी में एक महिला मिली जिसे उस व्यक्ति ने मिलवाया और कहा कि यह मेरी पत्नी है। व्यक्ति की पत्नी ने मुझसे कहा कि आपने मेरे साथ 6-7 महीने पहले दुष्कर्म किया है और यदि अब अपना

भला चाहते हो तो मेरा पति जैसा करे वैसे कर लो। उसके बाद उस व्यक्ति और महिला ने मिलकर 21 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो पूरे गांव में बदनामी कर दी जाएगी। इसके बाद जबरदस्ती उसका फोन छीनकर उसके खाते से कुल पांच हजार रुपए फोन पे से ट्रांसफर करवा लिए और उसके बाद एग्रिमेंट बनवाने के लिए दबाव भी बनाया। चार फरवरी को आरोपी व्यक्ति ने फोन करके धमकाया कि रुपयों की व्यवस्था कर दो।

यदि बेइज्जती से बचना चाहते हो तो 21 लाख रुपए दे दो। प्रार्थी ने जब उसने कहा कि इतने रुपए देने में वह असमर्थ है तो उसे सामाजिक बदनाम करने की धमकियां भी दी। आरोपियों ने दबाव बनाया कि लोग बदनामी से बचने के लिए एक करोड़ रुपए तक दे देते हैं 21 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है। आरोपियों के नहीं मानने पर अब परेशान होकर पीड़ित की ओर से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को परिवाद दिया गया है।

अजमेर, (कासं)। रेलवे द्वारा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में बढोतरी करने व स्टेशनों की बिल्डिंग को नया स्वरूप प्रदान करने की "अमृत स्टेशन योजना" के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। उत्तर-पश्चिम रेलवे पर अजमेर मण्डल के बिजयनगर स्टेशन सहित 77 स्टेशनों का लगभग 4 हजार करोड़ रूपये की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अन्तर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है।

बिजयनगर स्टेशन पर जारी कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर-पश्चिम रेलवे कैप्टन शशिकिरण तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक (गतिशील) अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत बिजयनगर स्टेशन पर 15.40 करोड़ रुपये से पुनर्विकास के कार्य अंतिम चरण में हैं। उन्होंने बताया कि पूरे स्टेशन भवन में सौंदर्य की कमी थी और उचित स्थान उपयोग की कमी थी, जिसे पूरे स्टेशन भवन के जीर्णोद्धार द्वारा सुधारा गया है। अब स्टेशन भवन अधिक विशाल और यात्री अनुकूल है। पूर्व में स्कूलेटिंग एरिया में बाहनों की



बिजयनगर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है।

आवाजाही के लिए सिंगल एंटी और एजिजट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्कूलेटिंग एरिया के नियोजित विकास, अलग एंटी/एजिजट और पार्किंग स्पेस में वृद्धि के माध्यम से इसमें सुधार किया गया है। इससे स्कूलेटिंग एरिया में बाहनों की आवाजाही में आसानी होगी और बाहनों का सही तरीके से आवागमन हो सकेगा। स्टेशन प्लेटफॉर्म की सतह को ऊपर उठाया गया है और दिव्यांगजनों के लिए स्पर्शनीय चिह्नों के

साथ सुधारा गया है तथा प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शैल्टर प्रदान किए गए हैं, जो गर्मी और बरसात के मौसम में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे। न वृक्षाल प्रतीक्षालय/हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो यात्रियों को आरामदायक प्रतीक्षा स्थान प्रदान करेगा। बुकिंग सुविधा के साथ न कॉन्कोर्स का निर्माण किया गया है। उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ और

■ बिजयनगर स्टेशन सहित 77 स्टेशनों का 4 हजार करोड़ की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अन्तर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है

स्टेशन पर जारी अमृत स्टेशन योजना के कार्यों की जानकारी हेतु एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन आज बिजयनगर स्टेशन पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर-पश्चिम रेलवे कैप्टन शशिकिरण, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गतिशील) अजमेर मंडल अनूप कुमार शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजमेर मंडल बीसीएस चौधरी, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर शेर सिंह मीना, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर विजेंद्र कुमार, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे कमल जोशी सहित अन्य रेल अधिकारी उपस्थित थे।

चोटिल पूजा वस्त्रकार, आशा शोभना डब्ल्यूपीएल से हुई बाहर

नई दिल्ली, 13 फरवरी। मुंबई इंडियंस (एमआई) की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की लेग स्पिनर आशा शोभना चोट के कारण वूमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2025 से बाहर हो गई हैं। मलेशिया में अंडर-19 विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य रही परसिका सिसोदिया और रेलवे की विकेटकीपर-बल्लेबाज नुजहत परवीन को क्रमशः एमआई और आरसीबी ने अपनी-अपनी टीमों शामिल किया है।

आईजीआई, हंसराज, खालसा, एसआरसीसी और एसपीएम कॉलेज ने जीते अपने-अपने मुकाबले

नई दिल्ली, 13 फरवरी। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, हंसराज कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने गुरुवार को 11वें पद्यश्री श्याम लाल मेमोरियल इन्वेंटेशनल हॉकी (महिला एवं पुरुष) टूर्नामेंट के लीग मुकाबलों में जीत दर्ज की। आज यहां खेले गये पहले मैच में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में किरोड़ी मल कॉलेज को 8-1 हराया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज की तरफ से फरमान और राम यादव ने दो-दो गोल किए और शेखर, सुमित, पुलकित और गुरमुख ने एक-एक गोल किया जबकि किरोड़ीमल कॉलेज की तरफ से एक गोल प्रजात आनंद ने किया। पुलकित को उनके शानदार खेल के लिए 'मैन ऑफ द मैच' से नवाजा गया।

हम चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सक्षम हैं : शांतो

दुबई, 13 फरवरी। बंगलादेश के कप्तान नजमुल हसन ने कहा है कि उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतो ने प्रसिद्धी टीमें को चेतावनी के लहजे में कहा है कि उनकी टीम आगामी टूर्नामेंट में खिताब जीतने की सोच के साथ मैदान में उतरेगी। शांतो का मानना है कि बंगलादेश की टीम का विश्वास बड़ रहा है और उन्हें भरोसा है कि उनकी टीम 19 फरवरी से पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले आठ टीमें के टूर्नामेंट में सबको चौका सकती है।

राजस्थान महिला अंडर-23 कैम्प में दौसा से दो महिला खिलाड़ियों का चयन

जयपुर, 13 फरवरी। जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय ने बताया कि राजस्थान की अंडर-23 महिला कैम्प में दौसा जिले से दो महिला खिलाड़ी निधि सैनी और याना वर्मा का चयन हुआ है। यह कैम्प आरसीए द्वारा 13 फरवरी से आरसीए एकेडमी में आयोजित किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ सचिव बृज किशोर उपाध्याय द्वारा यह बताया गया कि अब राजस्थान की टीम में प्रत्येक फॉर्मेट में दौसा जिले से खिलाड़ियों का कैम्प में और टीम में शामिल होना हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है। आगे और टीम में हमारे खिलाड़ियों की खेल में गुणवत्ता कैसे सुधरे इसका प्रयास किया जा रहा है इससे पूर्वी भी अंडर 19 महिला टीम में राजस्थान की ओर से दौसा जिले से 4 महिला खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया था जो कि दौसा जिले के लिए गौरव की बात है साथ ही जिला संघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा चयनित महिला खिलाड़ियों को बधाई दी गई और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चम्बल स्पोर्ट्स क्लब ने जयपुर ब्लूज को तीन विकेट से हराया

जयपुर, 13 फरवरी। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित के एल सैनी ए डिविजन लीग में आज खेले गए मैच में चम्बल स्पोर्ट्स क्लब ने जयपुर ब्लूज को 3 विकेट से हराया। के एल सैनी स्टेडियम पर खेले गए मैच में चम्बल स्पोर्ट्स ने टॉप जोकर पहले जयपुर ब्लूज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जयपुर ब्लूज ने सचिन जाट के 79 रन, हर्ष यादव के 31 रन, लखन भारती के 54 रन, कुलदीप खुरानिया के 40 रन व योगेंद्र काकोडिया के 19 रनों से 47.2 ओवर में 256 रन बनाए। चम्बल स्पोर्ट्स क्लब के लिए मिहित अग्रवाल ने 31 पर 3, यश पांडे ने 42 पर 3, दिव्यांश शर्मा ने 36 पर 2 व आर्यन जैन एक विकेट लिया। जवाबी पारी में चम्बल स्पोर्ट्स क्लब ने हार्दिक कुक्कड़ के 62 रन, राहुल खंडेलवाल के 17 रन, लोकेश सैनी के 20 रन, आर्यन जैन के 45 रन, श्रेय सक्सेना के 39 रन नाबाद व मिहित अग्रवाल के 35 रनों से 49.3 ओवर में 7 विकेट पर 259 रन बनाकर मैच जीत लिया। जयपुर ब्लूज के लिए महेश्वर पारीक ने 31 पर 2, राहुल चौधरी ने 40 पर 2, लखन भारती व हिमांशू राणा ने 1-1 विकेट लिया। 14 फरवरी को सुराणा क्रिकेट एकेडमी बनाम राजीव गांधी क्लब के मध्य मैच खेला जाएगा।

आईसीसी ने लगाया तीन पाकिस्तानियों पर भारी जुर्माना

नई दिल्ली, 13 फरवरी। आईसीसी ने पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया है। उसने शाहीन अफरीदी, सउद शकील और कामरान गुलाम को सजा सुनाई है। आईसीसी ने गुरुवार को एक्स के जरिए इसकी जानकारी शेयर की। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया था। इस मुकाबले के दौरान तीनों ने आईसीसी के नियमों को तोड़ा था। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान ये तीनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में आ गए थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिये टीम इंडिया के साथ नहीं जाएगा परिवार

बीसीसीआई की नई ट्रैवल पॉलिसी है वजह



नई दिल्ली, 13 फरवरी। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने परिवार को साथ नहीं ले जा सकते। दरअसल, बीसीसीआई की नई यात्रा नीति पहली बार इस टूर्नामेंट के जरिए लागू हो रही है। भारतीय टीम को पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेला है। इसके बाद 23 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से सामना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला दो मार्च को होना है।

रहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा, जबकि बाकी टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 शहरों में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को है, लिहाजा ये दौरा 3 हफ्ते से कम समय का ही है, जिसमें बीसीसीआई खिलाड़ियों के परिवार को साथ जाने की मंजूरी नहीं देगा। नई नीति के तहत 45 दिन या उससे लंबे दौर पर ही परिवार खिलाड़ियों के साथ अधिकतम दो हफ्ते के लिए जा सकता है। अगर कुछ बदलता है तो बात अलग है, लेकिन अभी तो खिलाड़ियों के साथ उनका परिवार नहीं जा रहा।

एक सीनियर खिलाड़ी ने इसके बारे में पूछा था लेकिन उसे बताया गया कि नई नीति का पालन किया जाएगा। बोर्ड की नीति में कहा गया है कि, विदेश दौर पर 45 दिन या उससे ज्यादा समय भारत से बाहर रहने पर खिलाड़ी की पत्नी और बच्चे अधिकतम दो सप्ताह के लिए साथ रह सकते हैं। इस नीति से अलग जाने पर उन्हें कोच, कप्तान और मैनेजमेंट से मंजूरी लेनी होगी। इससे इतर अवधि के लिए खर्च भी बोर्ड नहीं उठाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की 1-3 से हार के बाद ये नीति बनाई गई थी। निजी स्टाफ पहले टीम और कोचिंग ग्रुप के साथ रहता था। नए नियम के अनुसार, कोचिंग स्टाफ के एक सदस्य का निजी सचिव जो नियमित रूप से टीम होटल में रहता था अब अलग होटल में रहेगा। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि बोर्ड कुछ खिलाड़ियों की विशेष आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ शेफ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।



5वां रोशनलाल नैयर मेमोरियल राजस्थान ओपन टूर्नामेंट विपुल ने राज खत्री को हराया

जयपुर, 13 फरवरी। राजापार्क स्थित सिंह बिलियर्ड्स में आयोजित 5वां रोशन लाल नैयर मेमोरियल राजस्थान ओपन टूर्नामेंट में गुरुवार को खिलाड़ियों का प्रदर्शन में आज उलटफेर देखने को मिला। आज के मुख्य मैचों के स्कोर ऐसे रहे, आनंद को मनन ने 21-33, 59-49 से हराया, कुणाल ने प्रववी. की 64-66, 34-47 से हराया, विशाल ने युसुफ की 53-48, 28-44 से हराया, सनी ने सौरभ को 53-32, 46-52, 53-18 से हराया सु कुमार में बाबू को 64-28, 60-13 से हराया यश ने डा0 रमेश को 67-49, 10-42, 14-72 से हराया।

आज से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज, 5 टीमें के बीच 22 मुकाबले

नई दिल्ली, 13 फरवरी। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का 14 फरवरी से आगाज होने जा रहा है। टूर्नामेंट की पांच टीमों के बीच कुल 22 मैच खेले जाएंगे। इस सीजन का पहला मैच पिछले सीजन की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जयंट्स के बीच खेला जाएगा। बता दें कि, डब्ल्यूपीएल के अभी तक दो ही सीजन हुए हैं। साल 2023 में शुरू हुई इस लीग का पहला सीजन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई ने जीता था तो दूसरा सीजन 2024 स्मृति मंदाना की कप्तानी में आरसीबी ने जीता था। आरसीबी ने



2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था अब वह 2025 के सीजन के पहले मैच में गुजरात से भिड़ेगी। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में कुल 5 टीमें आपस में भिड़ेगी। जिसके तहत

राजस्थान रॉयल्स ने साईराज बहुतुले को स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया

पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रॉयल्स के कोचिंग सेंटअप में वापस लौटे। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ फिर से जुड़े

जयपुर, 13 फरवरी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सबसे प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी में से एक, राजस्थान रॉयल्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर साईराज बहुतुले को टीम के स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। 52 वर्षीय साईराज बहुतुले 2018-21 से सेटअप को हिस्सा रहे हैं और रॉयल्स में वापस लौटे हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अनुभव का खजाना है। भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक दिग्गज, बहुतुले के पास प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 630 से अधिक विकेट और 6,000 रन बनाने का प्रभावशाली रिकॉर्ड है। उन्होंने दो टेस्ट और आठ वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद से एक सफल कोचिंग करियर में तब्दील हो गए



हैं, जिसमें उन्होंने मुंबई, बंगाल, केरल और भारतीय राष्ट्रीय पुरुष टीम जैसी टीमों को सलाह दी है, जहाँ उन्होंने उभरती प्रतिभाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुतुले का फ्रेंचाइजी में स्वागत करते हुए, राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा: 'सैराज की रिपन गेंदबाजी की गहरी समझ और उनके व्यापक कोचिंग अनुभव ने उन्हें हमारी टीम के लिए एक अमूल्य जोड़ बना दिया है। युवा गेंदबाजों को सलाह देने की उनकी

26वें जयपुर विंटेज और क्लासिक कार एज्जीबिशन एंड ड्राइव का आयोजन 22 व 23 मार्च को

जयपुर, 13 फरवरी। राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से जयपुर के राज जय महल पैलेस में 22 और 23 मार्च को जयपुर विंटेज और क्लासिक कार एज्जीबिशन एंड ड्राइव का 26वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसकी घोषणा अशोक क्लब में राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की सामान्य बैठक में की गई। इस वर्ष शो में 100 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कारों शोकेस की जाएंगी, इनमें 100 साल से अधिक पुरानी कारों भी शामिल होंगी। ये कारें सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुडगांव, चंडीगढ़ और मुंबई सहित अन्य राज्यों से भी आयेंगी। यह जानकारी राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर के जनरल सेक्रेटरी, अविजित सिंह बदनोर ने दी।



इस अवसर पर राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब के संस्थापक अध्यक्ष, दर्शनिक कासलीवाल; उपाध्यक्ष, सुधीर कासलीवाल; सुधांशु कासलीवाल और हमीद गनी सहित क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इवेंट में फोर्ड मॉडल टी (1913), ऑस्टिन चम्मी (1923), रोल्स रॉयस (1934), कैडिलेक (1958), कैडिलैक बी16 (1931), शेवरेल इम्पाला (1958), पैकड कैबेलियर (1952) की इंग्रियल आदि जैसी कई अनूठी विंटेज और

क्लासिक कारें शामिल होंगी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में देशभर से कार प्रेमी, कार क्लब और ऑटोमोबाइल में रुचि रखने वाले लोग हिस्सा लेंगे। एज्जीबिशन 22 मार्च को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक निशुल्क रहेगी। 23 मार्च को इन कारों की ड्राइव निकाली जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आयोजन उन पुराने मैकेनिकों को रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रेरणा और उत्साह भी देता है, जिनका हुनर बदलती टेक्नोलॉजी और ऑटोमोशन के कारण बेकार हो गया है।

खिलाड़ी डिजिटल रिपॉजिटरी में करे अपने सर्टिफिकेट अपलोड स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्र के लिए 'डिजिटल रिपॉजिटरी' पोर्टल खिलाड़ियों को समर्पित

जयपुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्र के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया गया है। जिसमें खिलाड़ियों ने सर्टिफिकेट अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि अब रिपॉजिटरी पोर्टल खिलाड़ियों को उनके सभी खेल प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देगा, जिससे उन्हें भौतिक प्रमाण पत्रों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी एस.एस.ओ. आइडी पर लॉगिन करें, जहां स्पोर्ट्स व यूथ पर क्लिक करके जौट्टीसी आइडकोन पर क्लिक करें, जिसके बाद स्पोर्ट्स और यूथ पर क्लिक करें। इसके बाद अलग-अलग मोड दिखाई देंगे, जिसमें डिजिटल रिपॉजिटरी आईडन पर क्लिक करके जनाधार अपलोड कर देने के बाद अपने आप डिजिटल आ जायेगा। इसके बाद खिलाड़ी जिन प्रतियोगिताओं में खेले उनके सर्टिफिकेट अपलोड कर फिर सबमिट कर दें

खिलाड़ी डिजिटल रिपॉजिटरी में करे अपने सर्टिफिकेट अपलोड स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्र के लिए 'डिजिटल रिपॉजिटरी' पोर्टल खिलाड़ियों को समर्पित

जब आरसीए से खेल परिषद का एमओयू खत्म हो गया तो एकेडमी में होटल कैसे बिना एमओयू के संचालित हो रही है

होटल संचालक पर कौन मेहरबान ?

जयपुर, 13 फरवरी। आरसीए की ओर से कई करोड़ रुपए की बकाया धुगतान राशि नहीं देने के कारण खेल परिषद की ओर से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट अकादमी के ऑफिस, सवाई मानसिंह स्टेडियम और होटल को कब्जे में ले रखा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल परिषद के बीच स्टेडियम को लेकर हुआ एमओयू 22 फरवरी, 2024 को खत्म हो गया था। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद से इसकी समय अवधि आगे बढ़ाने की मांग की थी लेकिन खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की समय अवधि को आगे नहीं बढ़ाते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम और आरसीए एकेडमी को कब्जे में लिया था, इसको लेकर खेल परिषद सचिव ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें एमओयू खत्म होने के बाद फिर से एमओयू नहीं होने का हवाला



दिया था। वहीं शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया था जिसके बाद खेल परिषद ने कार्रवाई करते हुए स्टेडियम पर अपना कब्जा ले लिया और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर खेल परिषद ने ताले लगा दिए थे। अब सवाल यह उठता है कि जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जोकि सवाई मानसिंह स्टेडियम पर क्रिकेट का पुचारू संचालन करती थी उसे एमओयू के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन राजस्थान क्रिकेट एकेडमी में संचालित होटल जिसका एमओयू राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से था वो अब तक बिना किसी एमओयू के वहां कैसे संचालित हो रही है। जबकि

कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 गोल का अंतर्राष्ट्रीय पोलो मैच

जयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान पोलो क्लब ग्रांड्स पर 15 फरवरी को हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय पोलो मैच खेला जाएगा। 12 गोल का यह मैच भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीकी टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच मौजूदा पोलो सीजन का मुख्य आकर्षण होगा। भारतीय पोलो टीम का नेतृत्व हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह (3) करेंगे। टीम के अन्य सदस्य अभिमन्यू पाठक (3), शमशीर अली (3), सिमरन शेरालिंग (3) हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम में डंकन ली (2), टायसेन ओसुलिवन (4), जोहान डू प्रीज (4), उलरिच स्पाइज (2) शामिल होंगे। हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हर सीजन में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय पोलो मैच आयोजित किए जाएं। यह मैच गुलाबी नगर के पोलो प्रेमी दर्शकों के लिए एक बड़ा उपहार होगा। उन्होंने जयपुर में इस अंतरराष्ट्रीय मैच के आयोजन के लिए इंडियन पोलो एसोसिएशन (आईपीए) के मानद सचिव, कर्नल वीएस कहलॉ, वीएसएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने जयपुरवासियों से भी बड़ी संख्या में इस मैच के देखने के लिए आने का आग्रह किया।

खिलाड़ी हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के अंतरराष्ट्रीय पोलो मैच के आयोजन के लिए इंडियन पोलो एसोसिएशन (आईपीए) के मानद सचिव, कर्नल वीएस कहलॉ, वीएसएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने जयपुरवासियों से भी बड़ी संख्या में इस मैच के देखने के लिए आने का आग्रह किया।

पंकज सिंह जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एकेडमी में होटल का संचालन किस टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया? खेल परिषद ने कब एमओयू किया था लीज पर दिया? इससे होने वाली इनकम का कौन धनी-धोरी है? इसका पता नहीं चल पाया है। क्रिकेटोर्स के जीवन की तराशती राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेट्री और पंकज सिंह जैसे होनहार क्रिकेटर को स्टेडियम से बाहर का रास्ता दिखाने वाली खेल परिषद कैसे एमओयू राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से था वो अब तक बिना किसी एमओयू के वहां कैसे संचालित हो रही है। जबकि



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

‘राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65 % से अधिक वृद्धि की है’

मु.मंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि, राज्य सरकार ने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को व अडोबी जैसी कम्पनियों से साझेदारी की है। इससे बड़ी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल रहा है

जयपुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

शर्मा को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जैनपैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और जोधपुर में जैनपैक्ट में कार्यरत लगभग 8 हजार लोगों में 90 प्रतिशत से अधिक काम करने वाले स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जैनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्नीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।

जयपुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

शर्मा को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जैनपैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और जोधपुर में जैनपैक्ट में कार्यरत लगभग 8 हजार लोगों में 90 प्रतिशत से अधिक काम करने वाले स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जैनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्नीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।

जयपुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित किया और जैनपैक्ट के गठन के 20 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि जयपुर और जोधपुर में जैनपैक्ट में कार्यरत 8 हजार लोगों में से 90 प्रतिशत स्थानीय हैं।

प्रतिशत से अधिक काम करने वाले स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जैनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्नीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।

राहा है। जैनपैक्ट के सीईओ बी.के. कालरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में निवेश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट से निवेशकों के लिए राज्य में निवेश की नई राह खुली है। उन्होंने कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैनपैक्ट वर्तमान में राज्य में हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है तथा आगे भी प्रदेश के विकास में वे अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएंगे।

इस अवसर पर जैनपैक्ट के कंन्टी हैड पीयूष मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल सहित अधिकारीगण, जैनपैक्ट कंपनी के निवेश अधिकारीगण-विदेश से आए प्रतिभागी उपस्थित रहे।

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश

लोकसभा में जेपीसी प्रमुख जगदंबिका पाल और राज्यसभा में सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की

नई दिल्ली, 12 फरवरी। बजट से पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। हालांकि, इसके बाद ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति ने उनकी बात नहीं सुनी। तब इस विषय पर फिर से हंगामा हुआ।

राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों के भारी हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सदन की कार्यवाही

गौतम अडानी ने श्रीलंका के एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है, जिन्हें अडानी समूह ने भारतीय सरकार के कूटनीतिक दबाव के तहत प्राप्त किया था।

कंपनी को दो परियोजनाओं में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कुल 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना था और इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी थीं। अनुरा कुमारा प्रशासन अब इस परियोजना की समीक्षा कर रहा है। क्योंकि नए राष्ट्रपति बिजली की लागत को घटाना चाहते हैं। अदानी प्रीन एनर्जी लि. (ए.डी.जी.एल.) ने कहा, “हालांकि, हम श्रीलंका के प्रति प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में सहयोग के लिए तैयार हैं, यदि श्रीलंका सरकार चाहती है तो।”

तथापि, कोलंबो में, श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह प्रोजेक्ट में अडानी समूह अभी भी काम कर रहा है, जिसमें उसका 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा लगा हुआ है।

हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी।

धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है यह और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है यह और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

मार्ग को पूरा करने में असमर्थ, अडानी समूह प्रोजेक्ट से पीछे हट गया है। समूह ने 12 फरवरी को यह कहते हुए श्रीलंकाई सरकार को अपना निर्णय सूचित किया, कि उसे यह जानकारी मिली है कि परियोजना के प्रस्ताव पर पुनः बातचीत के लिए कैबिनेट द्वारा नियुक्त दो समितियाँ गठित की जाएंगी।

ए.डी.जी.एल. के बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार किया और निर्णय लिया कि, कंपनी श्रीलंका के संप्रभु अधिकारों और उसके विकल्पों का पूरी तरह से सम्मान करती है, तथापि, वह इस परियोजना से सम्मानपूर्वक पीछे हट गया है।

‘20 माह पहले ही लगा देते राष्ट्रपति शासन तो इतना नुकसान नहीं होता’

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन यदि 20 माह पहले ही लगा दिया होता तो वहां नागरिक हिंसा में मारे नहीं जाते और हजारों लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ता। पार्टी ने कहा है कि मणिपुर में आधिकारिक वही हुआ जिसकी मांग कांग्रेस पिछले 20 माह से कर रही है, अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मणिपुर में राष्ट्रपति

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ने कहा।

शासन लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में संविधानिक तंत्र के पूर्ण रूप से ठप्प हो जाने की बात कही, जिसके चलते 03 मई 2023 से अब तक 300 से अधिक लोगों की हत्या और 60,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का विस्थापन हुआ। यह तब हुआ है जब मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से क्षति पहुंचने दी गई। यह तब हुआ है जब फरवरी 2022 में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिला लेकिन उनकी राजनीति ने महज पंद्रह महीनों के भीतर इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया।

उन्होंने कहा यह तब हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति संभालने में पूरी तरह से विफल रहे जबकि इस दायित्व को प्रधानमंत्री ने उन्हीं सौंपा था और यह तब हुआ है जब दुनिया भर में घूमने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर जाने और वहां सुलह प्रक्रिया शुरू करने से लगातार इन्कार करते रहे।

कृषि उपज...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उक्त कार्यों पर स्वीकृत लागभ 24 करोड़ रुपये की राशि से कृषि उपज मण्डी समितियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, जिससे व्यापारियों एवं किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सम्पर्क सड़कों के निर्माण से किसानों एवं आमजन की मण्डी समिति तक पहुंच सुगम होगी। साथ ही, किसानों को कृषि जिनसों के विक्रय करने में समय एवं ईंधन की बचत भी होगी।

नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय नया इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा की थी

नई दिल्ली, 13 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया। यह बिल पुराने आयकर कानून से काफी अलग है। इस बिल के तहत टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को खासतौर पर कम करने की कोशिश की गई है। निर्मला सीतारमण ने सदन में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि नए बिल के तहत शब्दों की संख्या घटाई गई है। लोकसभा में पेश किए गए इस नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। जातव्य है कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नया आयकर बिल लेकर आ रही है।

नए टैक्स नियमों का बिल के पारित होने के बाद कई नए शब्दों का चलन बढ़ जाएगा। जैसे पहले फाइनेंशियल इंयर, प्रीवियस इंयर, असेसमेंट इंयर और ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल

अमेरिका में भारी समर्थन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तुलना में गैर-सहयोगी राज्यों और शहरों की संयोगी निधि रोकने के पक्ष में ज्यादा रुझान दर्शाया है। जातीय या नस्लीय पृष्ठभूमि को अनदेखा कर दें तो डेमोक्रेट्स टम्प की आप्रवासन नीतियों का भारी विरोध करते हैं। हालांकि, एशियाई (43 प्रतिशत) और अरबत (40 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स प्रशासन के निर्वासन प्रयासों का समर्थन करते हैं, जबकि श्वेत (32 प्रतिशत) और हिस्पैनिक (27 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स कम समर्थन दिखाते हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक विचारों का जातीय और नस्लीय समूहों के भीतर भी गहरा प्रभाव है, जो अमेरिका में आप्रवासन मुद्दों पर गहरे धुवीकरण को उजागर करता है।

जनता की टुंफ की आप्रवासन नीतियों पर राय राजनीतिक रुझान के अनुसार काफी भिन्न है। रिपब्लिकन और रिपब्लिकन-शुकाव वाले स्वतंत्र लोगों में 74 प्रतिशत लोग महसूस करते हैं कि प्रशासन निर्वासन के मामले में उचित कदम उठा रहा है, जबकि केवल 12 प्रतिशत को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है और 13 प्रतिशत का मानना है कि यह अत्यधिक है। इसके विपरीत, 73 प्रतिशत डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स-शुकाव वाले स्वतंत्र लोग मानते हैं कि प्रशासन निर्वासन के मामले में बहुत अधिक कर रहा है। केवल 21 प्रतिशत डेमोक्रेट्स को लगता है कि प्रयास पर्याप्त है, जबकि केवल 4 प्रतिशत मानते हैं कि प्रशासन पर्याप्त नहीं कर रहा है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहयोग में एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका की आधिकारिक कामकाजी यात्रा पर पहुंचे।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों और उद्योग जागत के नेताओं से मिलेंगे। पिछले महीने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के बाद उनसे मिलने वाले चौथे विदेशी नेता होंगे।

मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। बुधवार शाम को प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने पर ब्लेयर हाउस के पास बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

हादसा मध्यप्रदेश के भिंड जिले के बरहा गांव के पास हुआ। इसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई व एक दर्जन लोग घायल हो गए।

अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दतिया जिले के मगराी गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर 30 से 40 लोग कर रात्रि एक शादी समारोह में भिंड जिले के लहार आ रहे थे। ये सभी लड़की पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं।

अफसरों को घटाने के साथ क्यों उलझाया जा रहा है। राज्य सरकार के यह रुख अपनाते से हाई कोर्ट के गलतियों में और आमजन में भी यह आशंका फैल रही है कि याचिका खारिज करते ही सरकार जांच और गिरफ्तारियों के सिलसिले में हिलाई लायेगी। उल्लेखनीय है कि गहलौत सरकार के दौरान रीट पेपर लीक को लेकर अदालत ने याचिका दायर की गई थी। अदालत ने अपनी देखरेख में इसकी जांच एस.डी.जी. के अफसरों के राटोड़ को सौंपी थी।

सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के लिफ्ट होने का भी जिज्ञा किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने “अवैध पत्नी” व “रखैल” जैसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई

नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई। तलाक के मामले में हाईकोर्ट ने महिला के लिए “नाजायज पत्नी” और “वफादार मातृकन” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शीर्ष अदालत ने इसे महिला विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसी भाषा न केवल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग पूरी तरह अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि किसी महिला का विवाह अमान्य घोषित किया जाना एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे “अवैध पत्नी”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाह अमान्य होना कानूनी प्रक्रिया है पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप महिला को अवैध पत्नी कहें।

कहा जाए। अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 24वें पैराग्राफ में प्रयुक्त वफादार रखैल शब्द को भी कठोर शब्दों में खारिज किया।

शीर्ष अदालत ने इसे महिला अधिकारों और गरिमा का हनन बताया और कहा कि न्यायपालिका को अपने शब्दों के चयन में सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी भी वर्ग को गरिमा को ठेस न पहुंचे।

यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 से जुड़ा है। धारा 24 के तहत मुकदमे के लॉबत रहने तक भरण

पोषण और कार्यवाही के खर्च की व्यवस्था की जाती है, जबकि धारा 25 में स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परस्पर विरोधी विचारों पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से न्यायपालिका की निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर निष्पक्षता उठते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार चर्चा में है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अदालतों को न केवल कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्णय और टिप्पणियां किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। इस फैसले से न्यायपालिका में संवेदनशीलता और भाषा की शुद्धता को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है।

‘आर.पी.एस.सी. के अफसरों के पेपर लीक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याचिकाकर्ताओं द्वारा तब भी अदालत में नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद 16 दिसम्बर 2023 को नई सरकार ने घोषणा की थी कि पिछले गहलौत सरकार में आयोजित परीक्षाओं की जांच को रद्द किया जाएगा और राज्य सरकार ने एस.आई.टी. का गठन किया और फरवरी-मार्च 2024 में मामले में पहली एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि अधिकार याचिकाकर्ता इस जांच में एस.आई.टी. की सहायता भी कर रहे थे, परंतु ना तो परिणाम जारी करने के बाद, ना ही एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के बाद इन याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटबटायो। विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग डेढ़ साल तक कोई याचिका दायर नहीं की थी जिस दिन (13 अगस्त 2024) एस.ओ.जी. की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी तथ्य छुपाये कि वह सभी परीक्षा में अभ्यर्थी थे और पुलिस और एस.ओ.जी में भी कर्मचारियों के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने यह तथ्य बताकर यह बताते की

कोशिश की कि याचिकाकर्ता अवांछित कारणों से प्रेरित होकर याचिका दायर कर रहे हैं और इनमें से कई याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा के परिणामों को रद्द करने की गुहार नहीं की है, क्योंकि वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण थे और वह स्वयं लाभाभी रहेंगे अगर साक्षात्कार में कई उच्च रैंक वाले अभ्यर्थियों को हटा दिया जाये। हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं ने दस मई भर्ती परीक्षा-2022 को पणित: रद्द करने की गुहार की है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि गहलौ दिन से ही राज्य सरकार ने मामले की जांच शुरू करने के लिये एस.आई.टी. गठित कर दी थी और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच करवा रही है, परंतु जांच में हुए तथ्य सामने आना कि आर.पी.एस.सी. के अफसर भी पेपरलीक में शामिल हो सकते हैं या नहीं, से मामला जटिल हो गया है क्योंकि आर.पी.एस.सी. के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराई गई जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह का कहना था कि अगर राज्य सरकार तुरंत ही परीक्षा निरस्त करती है तो गिरफ्तार किये गये अफसरों की देखरेख में आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित

परीक्षाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जायेगा और फिर सरकार को उन सभी परीक्षाओं की भी निरस्त करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटिशन 13 अगस्त 2024 को दायर की गई थी लेकिन इसका रिट स्ट्रुटेशन 20 अगस्त को हुआ था। तथ्यों के अनुसार, 31 अगस्त को अधिकारी रामू राम रायका की पुत्री और बेटे को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था फिर 1 सितम्बर का रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया था। फिर 2 सितम्बर को आर.पी.एस.सी.

अफसर बाबू लाल कटारा को भी गिरफ्तार किया गया था। यहां गौर फरमाने योग्य है कि दोनों गिरफ्तारियों के बाद भी महाधिवक्ता ने 5 सितम्बर 2024 को गृह विभाग को अपनी विधिक सलाह दी थी कि परीक्षा को रद्द किया जा सकता है जो गृह विभाग को 14 सितम्बर को मिली थी।

मामले से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि महाधिवक्ता के समक्ष इस मामले की जांच और कानूनी जटिलताओं की संपूर्ण पृष्ठभूमि स्पष्ट थी और इसके बावजूद उन्होंने परीक्षाओं को रद्द करने की सलाह दी। इन अधिवक्ताओं का कहना था कि परीक्षा को रद्द करने और आर.पी.एस.सी.